



विश्व के सरी

सिर्फ पत्रकारिता...

आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ सोल विबलडन: जेवरेव ने रॉयल को हराया...

@ विचार लोकतंत्र अंकुश रखे अफसरतंत्र पर...

@ व्यापार

कमजोर डॉलर से सोने और चांदी में तेजी...

@vishwakesariTV

@vishwakesari

vishwa_kesari_official

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जापान आर्थिक मंच पर रखा भविष्य का विजन

व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

एजेंसी ■ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए दोनों देशों के मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक रिश्तों पर जोर दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जापान जॉइंट इकॉनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ यहां मंच में उपस्थित होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पीएम ने कहा कि यहां मौजूद कई कंपनियां दशकों से भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ तो एक सदी से भी ज्यादा समय से भारत की विकास यात्रा का हिस्सा रही हैं। और जो नए साझेदार इस मंच को जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत-जापान



की इस सफलता की कहानी का हिस्सा बनने पर दिल से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि? भारत और जापान का रिश्ता वाकई बहुत खास है। हमारी आर्थिक साझेदारी की कई शानदार मिसालें हैं। अभी

थोड़ी देर पहले हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए मैनुफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। आज सुजुकी की दुनिया भर में बनने वाली करीब दो-तिहाई गाड़ियां भारत में बनती हैं और 100

से ज्यादा देशों में निर्यात होती हैं। संबोधन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम ताकाइची से कहा, 'मुझे बताया गया है कि आपकी मोटर बाइक का बहुत शौक है।

मुख्य बातें



दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते दशकों पुराने और भरोसे पर आधारित



मारुति सुजुकी का नया प्लांट भारत-जापान साझेदारी की मिसाल



कावासाकी, यामाहा, होंडा की बाइक्स भारत से दुनिया भर में निर्यात



भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही, लगातार आर्थिक सुधार जारी



पीएमओ करेगा 'जापान बिजनेस वीक' का आयोजन

13 हजार करोड़ की मेट्रो परियोजना का शिलान्यास



एजेंसी ■ जयपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले के पंचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह के दौरान 13,037 करोड़ रुपए की जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 का शिलान्यास करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह महत्वाकांक्षी परियोजना जयपुर में शहरी परिवहन

व्यवस्था को नई दिशा देगी और शहर के प्रमुख औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को तेज एवं आधुनिक मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगी।

जयपुर मेट्रो फेज-2 के तहत प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण (नॉर्थ-साउथ) मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।

यह कॉरिडोर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया (वीकेआईए), जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टॉक रोड, सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, जयपुर रेलवे स्टेशन, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ेगा। फेज-2 परियोजना के तहत कुल 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे जयपुर के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख रियायती इलाकों के बीच बेहतर और तेज सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना का निर्माण राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमआरसीएल) करेगा, जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की 50:50 संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) कंपनी है।

रक्षा खरीद परियोजनाओं को सरकार की हरी झंडी, 52 हजार करोड़ की मंजूरी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

देश के सशस्त्र सैन्य बलों को और अधिक आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 52,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत रक्षा खरीद परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी (एओएन) प्रदान की गई।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में स्वीकृत इन प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की



युद्धक क्षमता, निगरानी व्यवस्था, वायु रक्षा और भविष्य के युद्धक्षेत्र

की चुनौतियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है। डीएसी ने

भारतीय सेना के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग', मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली शामिल हैं।

'आकाश तरंग' प्रणाली सेना की अग्रिम तैनातियों और महत्वपूर्ण

सैन्य ठिकानों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह प्रणाली ड्रोन का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। वहीं, एंटी-टैंक मिसाइल से इन्फैंट्री की ताकत बढ़ेगी। मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली सेना की इन्फैंट्री टुकड़ियों को दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाएगी। इससे अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

भारत का लक्ष्य 1 ट्रिलियन

डॉलर का निर्यात हासिल करना है: पीयूष गोयल



नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 1 ट्रिलियन डॉलर (एक लाख करोड़ डॉलर) के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 863 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ हासिल करने का प्रयास है।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में मर्चेंडाइज (वस्तु) निर्यात को लगभग 530 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 40 की मौत



एजेंसी ■ खेटी

खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी कि बलूचिस्तान के शेरानी जिले के धनसार इलाके से निकलकर प्रांतीय सीमा पार कर खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में घुसते ही पेशावर जा रही एक यात्री बस खाई में गिर गई।

पाकिस्तान की मीडिया डॉन के अनुसार, इस भयानक घटना में 40

लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के मीडिया और राजनीतिक मामलों के सहायक, शाहिद रिंद ने सबसे पहले मरने वालों की संख्या बताई। हालांकि, बाद में केपी रेस्क्यू 1122 ने भी इसकी पुष्टि की।

रिंद के बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती के निर्देश पर दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। शुक्रवार सुबह बयान में कहा गया, 'दोनों प्रांतों के जिला प्रशासन,

बचाव और दूसरे संबंधित विभाग प्रभावित लोगों को मदद दे रहे हैं। सच सामने लाने के लिए घटना की जांच की जाएगी।

केपी रेस्क्यू 1122 के एक बयान में कहा गया कि झोब इमरजेंसी सर्विस और रेस्क्यू 1122 की टीमें दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचीं और बचाव का काम शुरू किया। आठ घायलों को इलाज के लिए झोब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (डीएचक्यू) ले जाया गया। इसके अलावा शवों को पहले पास के एक ग्रामीण हेल्थ सेंटर भेजा गया और फिर बाद में शवों को झोब डीएचक्यू ले जाया गया।

इसमें यह भी बताया गया कि जब बस खाई में गिरी तो उसमें 48 यात्री सवार थे। डॉन के अनुसार, जोब में इमरजेंसी सेंटर के प्रमुख सनाउल्लाह शेरानी ने बताया कि बस लगभग 70 से 80 फीट नीचे खाई में गिर गई।

भारत की आर्थिक सफलता का ट्रंप ने किया जिक्र

एजेंसी ■ वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बताया और कहा कि अमेरिका को महंगाई और इंटरेस्ट रेट की चिंताओं से बंधे रहने के बजाय बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हासिल करना चाहिए।

सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन की



सराहना की, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर अमेरिकी फेडरल

रिजर्व की बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को लेकर आलोचना की।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'आपके पास कुछ देश हैं, भारत उनमें से एक है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह 7, 8 फीसदी पर है। हमें ऊपर बढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं, तो वे इसे खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका को बहुत तेजी से आर्थिक विस्तार का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें 4 फीसदी पर रुकना चाहिए।

राम मंदिर विवाद पर केजरीवाल के तीखे आरोप

एजेंसी ■ नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। गोवा दौरे के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े कथित घोटालों में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और अब तक की गई कार्रवाई केवल दिखावे के लिए है।

केजरीवाल ने कहा कि देशभर



के करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा के साथ दान दिया था, लेकिन अब

मंदिर से जुड़े कथित जमीन सौदों, निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी और चढ़ावे की चोरी जैसी खबरों से

लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं के गायब होने की बातें सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार चोरी की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद मामले को दवाने का प्रयास किया गया। वर्ष 2021 से ही मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में अनियमितताएं सामने आई थीं।

सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा, विश्व बैंक के सहयोग से दिल्ली में शुरू होगी 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना

एजेंसी ■ नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना शुरू करने जा रही है। यह पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा।

इसका उद्देश्य दिल्ली की वायु प्रदूषण मिटिगेशन प्लान को तेजी से लागू करना, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और 'विकसित भारत 2047' के विजन में योगदान देना है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि



कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की

जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत

8,300 करोड़ रुपए है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं है, बल्कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक दीर्घकालिक निवेश है।

‘विकसित दिल्ली’ के लिए मास्टर प्लान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डीडीए के साथ एलजी टीएस संधू ने की बैठक

विश्व केसरी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आगामी मास्टर प्लान और सतत शहरी विकास की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की गई।

उपराज्यपाल संधू ने राष्ट्रीय राजधानी की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक आधारित समाधानों पर जोर दिया।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि डीडीए की इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे।

अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करते हुए संधू ने एक्स पर लिखा, ‘डीडीए को निर्देश दिया गया है कि अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ ज़ोरों टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसके लिए जमीन और भवनों की रियल-टाइम निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए, ताकि ऐसे मामलों का तुरंत पता लगाकर त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा, ‘मैंने दोहराया कि दिल्ली की बदलती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक, पारदर्शी और तकनीक आधारित दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। हमने एक टिकाऊ, मजबूत और रहने योग्य ‘विकसित दिल्ली’ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।’

उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा, ‘मैंने



डीडीए की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी भी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी विकास की रूपरेखा की समीक्षा की गई। ‘ उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के आगामी मास्टर प्लान, नागरिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने तथा शहर के सुनियोजित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार विकास को सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे पहले गुरुवार को उपराज्यपाल ने ओमान से आए छात्रों के साथ हुई मुलाकात की जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा, ‘ओमान से आए प्रतिभाशाली छात्रों के एक समूह से बातचीत कर खुशी हुई। ये छात्र आईआईटी गांधीनगर में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित ‘शास्त्र प्रतिभा प्रतियोगिता’ के विजेता हैं। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और खोजी सोच को देखकर उत्साहवर्धन हुआ।

मानसून को लेकर अलर्ट मोड में एनडीआरएफ, महाराष्ट्र और गोवा में की टीमों की पूर्व तैनाती

विश्व केसरी ■ **पुणे।** मानसून 2026 के मधेनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। इसे लेकर एनडीआरएफ की 5वीं वाहिनी ने महाराष्ट्र एवं गोवा के विभिन्न जिलों में कई टीमों की पूर्व तैनाती की है।

दरअसल, मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी और तुरंत निपटने के मकसद से नेशनल डिजास्टर रिसर्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की पुणे स्थित 5वीं वाहिनी ने 1 जुलाई से ही महाराष्ट्र और गोवा के कई संवेदनशील जिलों में अपनी टीमों तैनात कर दी हैं।

यह तैनाती राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), महाराष्ट्र तथा एनडीआरएफ मुख्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, धाराशिव, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, मुंबई, नागपुर और उत्तर गोवा में की गई है। ये टीमों पूरे मानसून अवधि

तक महाराष्ट्र और गोवा के इन संवेदनशील जिलों में तैनात रहेंगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुणे स्थित एनडीआरएफ की पांचवीं बटालियन के कमांडेंट संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र एवं गोवा, 5वीं वाहिनी का प्राथमिक कार्यक्षेत्र है। टीमों की तैनाती संबंधित क्षेत्रों की भौगोलिक संवेदनशीलता, पूर्व वर्षों के आपदा अनुभव तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

उन्होंने कहा कि रणनीतिक पूर्व तैनाती से आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे बचाव एवं राहत कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जा सकते हैं। सभी टीमों अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों, बाढ़ राहत संसाधनों तथा प्रशिक्षित कार्मिकों से सुसज्जित हैं और जिला प्रशासन सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि एनडीआरएफ प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ नागरिकों की सुरक्षा और समयबद्ध राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

16वें वित्त आयोग से झारखंड की पंचायतों को 14,231 करोड़ रुपए मिलेंगे, केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग

विश्व केसरी

रांची/नई दिल्ली। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं को करीब 14,231 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिलेगा।

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इस राशि से राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कार्यशाला में झारखंड



कहा कि प्रस्तावित अनुदान में 11,385 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ रुपए परफॉर्मंस ग्रांट के रूप मिलने हैं, लेकिन परफॉर्मंस ग्रांट तय करते समय झारखंड जैसे राज्यों की वास्तविक परिस्थितियों और सीमित राजस्व क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने आयोग से इस मामले में उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया, ताकि अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों की पंचायतों को भी विकास के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की लंबित अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि पंचायतों में पहले से चल रही विकास योजनाएं प्रभावित न हों।

साथ ही 16वें वित्त आयोग की अनुदान राशि भी समय पर जारी की जाए। उन्होंने पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने और स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायतों को मजबूत किए बिना ग्रामीण विकास के लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते।

अमित शाह से मुलाकात के दौरान पंजाब की कानून-व्यवस्था पर हुई चर्चा: सुखजिंदर सिंह रंधावा



एक पत्र लिखा था, जिसमें पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई थी। पत्र में गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों की सक्रियता, लोगों को मिल रही धमकी भरी कॉल्स, रंगदारी के ज़रिए की जा रही लूट और अपराध की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया था। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि जेलों के भीतर से 24 घंटे मोबाइल फोन संचालित हो रहे हैं। जेल से मोबाइल चलना देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यदि जेलों के भीतर से आतंकवाद और गुंडागर्दी से जुड़ी गतिविधियों पर बातचीत हो रही है और वहाँ से पूरे नेटवर्क को संचालन किया जा रहा है।

कानूनी-व्यवस्था पर कोई संबंध नहीं है। कुछ रिपोर्टों में उनकी मुलाकात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि यह बैठक पूरी तरह पंजाब की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। रंधावा ने बताया कि उन्होंने 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

कानून-व्यवस्था पर कोई संबंध नहीं है। कुछ रिपोर्टों में उनकी मुलाकात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि यह बैठक पूरी तरह पंजाब की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। रंधावा ने बताया कि उन्होंने 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

कानून-व्यवस्था पर कोई संबंध नहीं है। कुछ रिपोर्टों में उनकी मुलाकात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि यह बैठक पूरी तरह पंजाब की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। रंधावा ने बताया कि उन्होंने 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं, यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है: संगमा

विश्व केसरी

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को जलवायु परिवर्तन को 'अस्तित्वगत संकट' बताया और अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जून में मेघालय में बारिश में 80 प्रतिशत से अधिक की चिंताजनक कमी दर्ज की गई है।

संगमा यहां 'अल नीनो की तैयारी के लिए राज्य की प्रतिक्रिया विकसित करना: खाद्य और जल सुरक्षा को मजबूत करना' विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं है; यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है। पूर्वानुमान भले ही



तात्कालिक वास्तविकता है, जिसके लिए सरकारों, समुदायों और संस्थानों को मिलकर तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चुनौती नहीं है; यह हमारी वर्तमान वास्तविकता है। पूर्वानुमान भले ही

बदल जाएं, लेकिन तैयारी में देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य मौसम पूर्वानुमान में सुधार की प्रतीक्षा में कार्रवाई में देरी नहीं कर सकता। जून माह में दर्ज की गई भारी वर्षा की कमी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पेयजल

उपलब्धता और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए स्थिति में सक्रिय योजना बनाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे शमन उपायों को लागू करते समय लचीला, डेटा-आधारित और अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएं, और कहा कि आज उठाया गया हर कदम आने वाली पीढ़ियों की सहनशीलता को निर्धारित करेगा। हम परिपूर्ण योजनाओं का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। आज उठाया गया हर कदम आने वाली पीढ़ियों की सहनशीलता को आकार देगा। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के एक प्रमुख घटक के रूप में सतत कृषि पर प्रकाश डालते हुए संगमा ने कहा कि मेघालय की

प्राकृतिक खेती संबंधी पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करती है, लेकिन उन्होंने मेघालय की अनूठी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल कृषि पद्धतियों में नवाचार और विकास की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने दीर्घकालिक जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, बांधों और जलाशयों का निर्माण तथा अन्य जल-संरक्षण संरचनाओं जैसे एकीकृत उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

नकटी विस्थापितों का मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव, भारी पुलिस बल तैनात

विश्व केसरी■

रायपुर। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में विस्थापित ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण रायपुर पहुंचकर मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी बंगले का घेराव करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत शंकर नगर को ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से को भी बंद कर दिया गया, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित रहा।

इससे पहले ग्रामीण रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे, जहां कांग्रेस नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।

गौरतलब है कि नकटी गांव में करीब 80 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के तीन दिन बाद भी विरोध धमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पूर्व



उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। वहीं भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में घर तोड़ना गलत है और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आज भी ग्रामीणों के साथ खड़े हैं।

7.14 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ की प्रोत्साहन राशि



विश्व केसरी■

रायपुर। सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए 162.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि वितरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वन धन विकास समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। साथ ही वन धन विकास केंद्रों के पांच नए हर्बल उत्पादों का लोकार्पण तथा 'वन धन विकास केंद्र : आदिवासी सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर, छत्तीसगढ़' पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका और आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि संग्राहकों की मेहनत का लाभ सीधे उनके खातों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 13.50 लाख लघु वनोपज संग्राहक परिवारों को पारिश्रमिक, लाभांश, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, चरणपादुका वितरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि सरकार इमली, महुआ, साल बीज, हर्षा, बहेरा और चिरौजी जैसे लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन और

विपणन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के 155 वन धन विकास केंद्र स्थानीय महिलाओं और स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। कार्यक्रम में गरियाबंद, महासमुद्र, कटघोरा, नारायणपुर, जशपुर, जगदलपुर, धमतरी और कांकेर के उत्कृष्ट संग्राहकों, वन धन विकास समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को विभिन्न पुरस्कार एवं लाभांश राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। सरकार ने सहकारिता आधारित विकास के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

संक्षिप्त खबरें

IGKV छात्रावास में छत गिरने से छात्र घायल, NSUI का प्रदर्शन



रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में छत का हिस्सा गिरने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में छात्र के निर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे टांके लगाने पड़े। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव महताब हुसैन के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और कुलपति की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान महताब हुसैन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रावासों की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि यदि समय रहते मरम्मत कराई जाती, तो यह हादसा नहीं होता। एनएसयूआई ने छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए स्वीकृत बजट, उसके उपयोग तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय तकनीकी और वित्तीय जांच कराने की मांग की है। संगठन ने छात्र कल्याण अधिष्ठाता, इंजीनियरिंग शाखा सहित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की भी मांग की है। साथ ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय छात्रावासों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग भी उठाई गई है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और छात्रावासों की स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध:मंत्री टंक राम वर्मा

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बलौदाबाजार- भाटापारा जिला के बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए 44 लाख रुपये की लागत वाले तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। मंत्री वर्मा ने कहा कि सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आज गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों में खुशहाली और समृद्धि का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। राजस्व मंत्री ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम देवरी में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित चेक डैम का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए 16 लाख रुपये की लागत से बने भव्य 'महतारी सदन' भवन का उद्घाटन तथा सामुदायिक आयोजनों की सुविधा के लिए 8 लाख रुपये की लागत से बनने वाले शेड निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई।

चार साल से फरार मानव तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को 20 हजार में बेचने की साजिश का आरोप

रायगढ़। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत धरमजयगढ़ पुलिस को मानव तस्करी के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 से फरार चल रहे आरोपी रामा चौहान को जशपुर जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, जून 2022 में धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बालिका को मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले से सुरक्षित बरामद किया। विवेचना में खुलासा हुआ कि चार आरोपियों ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को राजस्थान ले जाकर 20 हजार रुपये में बेचने की साजिश रची थी।

इस मामले में पुलिस पहले ही



तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपियों में शामिल रामा चौहान लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जशपुर जिले के ग्राम जोराडोल में दबिश देकर आरोपी रामा चौहान को गिरफ्तार किया। पृच्छाछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा।

रथयात्रा पर यात्रियों के लिए राहत, टीओडी स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध हैं रिक्त बर्थ

विश्व केसरी■

रायपुर। रथयात्रा के दौरान बढ़ी हुई यात्री भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन ऑन डिमांड (टीओडी) स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। इन विशेष ट्रेनों में फिलहाल रिक्त बर्थ उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अवसर मिल सकेगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नियमित ट्रेनों में भीड़ से बचने के लिए टीओडी स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध बर्थ का लाभ उठाएं। टिकट आरक्षण से पहले यात्री अधिकृत रेलवे आरक्षण केंद्रों तथा आईआरसीटीसी के माध्यम से सीटों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि यात्री रेलवेन ऐप के जरिए आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट



बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति, कोच पोजिशन सहित अन्य रेलवे सेवाओं का भी लाभ आसानी से ले सकते हैं।

रेलवे के अनुसार यात्रियों की मांग और बुकिंग की स्थिति के आधार पर विशेष ट्रेनों के संचालन की लगातार समीक्षा की जा रही

है। यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिकता है।

जितेन्द्र कुमार नेताम को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार



विश्व केसरी■

रायपुर। राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रमुख अभियंता जितेन्द्र कुमार नेताम को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के पद पर कार्यरत जितेन्द्र कुमार नेताम अपने वर्तमान

दायित्वों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का कार्यभार भी संभालेंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस निर्णय को विभागीय कार्यों में निरंतरता बनाए रखने तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेताम के अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद विभाग के प्रशासनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।

वीबी-जी राम-जी अधिनियम से ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया आधार

विश्व केसरी■

रायपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) रायपुर ने शुक्रवार को न्यू सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम-जी] अधिनियम, 2025 पर मीडिया वार्ता आयोजित की। कार्यक्रम में अधिनियम के उद्देश्यों, प्रमुख प्रावधानों, वित्तीय व्यवस्था, क्रियान्वयन तंत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावित प्रभावों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद

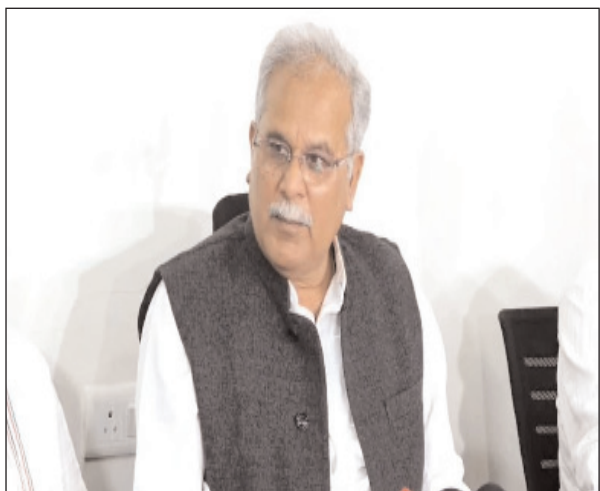


लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि विकसित वीबी-जी राम-जी अधिनियम से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि

आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा पलायन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज आधारित गतिविधियों, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में पूर्ववर्ती प्रणाली की तकनीकी और प्रक्रियागत कमियों को दूर किया गया है। अधिनियम के तहत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है तथा मजदूरी दर में भी वृद्धि का प्रावधान किया गया है। जाँच कार्डधारकों को समयबद्ध रोजगार

उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में बताया गया कि सभी विकास कार्यों का विवरण ऑनलाइन पोर्टलों पर उपलब्ध रहेगा। कार्यों की जियो-टैगिंग के माध्यम से नियमित निगरानी होगी और अनियमितता मिलने पर जांच व कार्रवाई की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दूरसंचार अवसंरचना विकसित की जाएगी। ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की प्रस्ताव तैयार करेंगी, जिनका जनपद और जिला स्तर पर परीक्षण व अनुमोदन होगा।

भाजपा वरिष्ठ नेताओं की राजनीति खत्म करने में लगी है, बृजमोहन को भी निशाना बनाया जा रहा : भूपेश बघेल



विश्व केसरी■

रायपुर। नकटी गांव में बेदखली की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति 'बृजमोहन अग्रवाल बनाम भाजपा' जैसी बन गई है। भाजपा के भीतर यह षड्यंत्र चल रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल की राजनीति को

किस तरह समाप्त किया जाए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल विपक्ष से ही नहीं, बल्कि अपने ही वरिष्ठ नेताओं को भी कमजोर करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राजनीतिक भूमिका को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। बघेल के अनुसार, भाजपा के अंदर चल रही यह खौफनाक अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है और नकटी बेदखली का मामला भी इसी का एक उदाहरण है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के भीतर की अंदरूनी राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाने की रणनीति पार्टी के लिए भविष्य में नुकसानदायक साबित होगी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है।

संपादकीय

जब शहर तपते हैं



डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत आज तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन—दो ऐसी प्रक्रियाओं के संगम पर खड़ा है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। एक ओर शहर विकास, रोजगार और नवाचार के केंद्र हैं, तो दूसरी ओर वे बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, शहरी बाढ़, जल संकट, वायु प्रदूषण और चरम मौसमी घटनाओं के सबसे बड़े शिकार भी बनते जा रहे हैं। सामान्यतः जलवायु परिवर्तन को पर्यावरणीय समस्या माना जाता है, किंतु भारतीय शहरों का अनुभव बताता है कि यह केवल प्रकृति का संकट नहीं है; यह शहरी शासन, सामाजिक न्याय और विकास मॉडल की सीमाओं को उजागर करने वाला बहुआयामी संकट है।

इस संकट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, जो शहरों की अर्थव्यवस्था और जीवन-प्रणाली को प्रतिदिन संचालित करते हैं, लेकिन नीतियों और योजनाओं में सबसे पीछे रह जाते हैं। इनमें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, प्रवासी मजदूर, सड़क विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले और स्वच्छता कार्यकर्ता प्रमुख हैं। विडंबना यह है कि जिन लोगों के श्रम से शहर चलते हैं, वही लोग जलवायु परिवर्तन के सबसे असुरक्षित शिकार बनते हैं।

भारत की लगभग 35 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और आने वाले दशकों में यह अनुपात तेजी से बढ़ेगा। शहरों का विस्तार अक्सर बिना समुचित योजना के हुआ है। हरित क्षेत्रों का सिक्कुटना, जल निकायों का अतिक्रमण, अनियंत्रित कंक्रीटीकरण और कमजोर जल निकासी व्यवस्था ने शहरों की प्राकृतिक जलवायु सहनशीलता को कम कर दिया है।



परिणामस्वरूप थोड़ी सी अधिक वर्षा भी व्यापक जलभराव और बाढ़ का कारण बन जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने पर गंभीर जल संकट उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते तापमान ने शहरी 'हीट आइलैंड' प्रभाव को और तीव्र बना दिया है, जिससे शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो जाते हैं।

यह स्थिति केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं है। यह शहरी शासन की कमियों को भी दर्शाती है। अनेक नगर निकायों के पास न तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और न ही जलवायु परिवर्तन के अनुरूप दीर्घकालिक योजना बनाने की क्षमता। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, डेटा आधारित निर्णयों की कमी और अल्पकालिक विकास परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता ने समस्या को और जटिल बना दिया है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को अब 'क्लाइमेट जस्टिस' अर्थात् जलवायु न्याय के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जिन लोगों का कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है, वही इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विभिन्न आकलनों के अनुसार शहरों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हैं। उनके पास स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसी सुविधाएँ नहीं होतीं। उनकी आय प्रतिदिन के कार्य पर निर्भर करती है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन उनके लिए केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आजीविका का संकट बन जाता है।

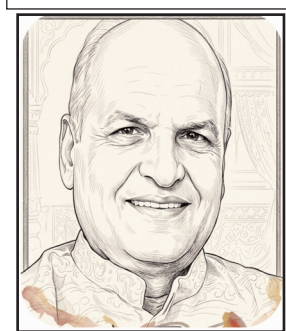
जब भीषण गर्मी पड़ती है, निर्माण कार्य धीमे हो जाते हैं, सड़क विक्रेताओं की बिक्री घट जाती है, रिक्शा और ई-रिक्शा चालक कम समय तक काम कर पाते हैं तथा दिहाड़ी मजदूरों की आय प्रभावित होती है। दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा और शहरी बाढ़ से बाजार बंद हो जाते हैं, परिवहन बाधित होता है और लाखों लोगों की रोजी-रोटी टप पड़ जाती है। अधिकांश अनौपचारिक श्रमिकों के पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होता। परिणामस्वरूप वे कच्चे, भूख और आर्थिक असुरक्षा के दुष्चक्र में फंस जाते हैं।

शहरों की झुग्गी बस्तियाँ जलवायु संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं। अधिकांश झुगियाँ नदी किनारे, नालों के आसपास या निम्न-स्तरीय भूमि पर स्थित होती हैं, जहाँ बाढ़ और जलभराव का खतरा अधिक रहता है।

एक सामयिक चिंतन

लोकतंत्र अंकुश रखे

अफसरतंत्र पर !



गिरीश पंकज

यह लोकतंत्र की विफलता है कि यहाँ अफसर जनप्रतिनिधियों से ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। दरअसल जो तथाकथित बड़े अफसर होते हैं, वे बड़े चालाक होते हैं। जनप्रतिनिधियों को 'तरह-तरह की सुविधाएँ' देकर एक तरह से उन्हें खरीद लेते हैं। इसलिए उनकी बोलती बंद हो जाती है। जो जनप्रतिनिधि दबंग होते हैं, वे अफसरों को टाइट रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। बाकी तो अफसर के सामने एकदम बेबस हो जाते हैं। अकसर निरीह होकर कहते रहते हैं, 'क्या करें,अफसर हमारी सुनते नहीं।' अगर अफसर नहीं सुनते, तो फिर काहे का लोकतंत्र? काहे के जनप्रतिनिधि? फिर तो यह अफसर तंत्र हो गया!

मेरा यह चिंतन भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी और व्यावहारिक हकीकत को बयां करता है। जिसे हम सामान्य बोलचाल में अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वह कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों पर इतनी हावी हो जाती है कि आम जनता को 'लोकतंत्र' और 'अफसरतंत्र' में फेरबदल क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण अकसर कमजोर जनप्रतिनिधि हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह कड़वी सच्चाई है कि जो अफसर को टाइट नहीं रख सकता, वो अक्सर उसकी दी हुई सहूलियतों का कर्जदार हो जाता है। अफसर जनप्रतिनिधियों को सुख-सुविधाओं और प्रोटेक्टोकोल के जाल

में उलझा देते हैं। ?लकजरी गाड़ियाँ, बंगले, दौरों के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट और रिस्तेदारों के छोटे-मोटे काम करवाकर अफसर राजनेताओं को एक 'कम्फर्ट जोन' में ले आते हैं। फिर उनको यही जीवन रस आने लगता है और वे अफसरों पर आश्रित हो जाते हैं।



अब समय आ गया है कि ब्यूरोक्रेसी को कसने के लिए एक नागरिक समिति बने, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त रहे. वह समय समय पर ब्यूरोक्रेसी को न केवल फटकारे वर्ग वरन उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री तक अनुशंसा भी करे. ऐसे ही सुधारात्मक पहल से ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित किया जा सकता है।

हालत यह होती है कि किसी निर्माण कार्य के लिए आवंटित राशि में कमोशन का हिस्सा अफसर अधिक रख लेता है जनप्रतिनिधि को कम देता है. ?जब जनप्रतिनिधि सुविधा का आदी हो जाता है या अपने निजी हितों के लिए अफसर की मदद लेने लगता है, तो तो उसकी नैतिक ताकत उसकी ख त्त

फिर वे खुद नियमों के बहुत पक्के होते हैं। समस्या यह है कि डराने-धमकाने वाली 'दबाव' से काम कुछ समय के लिए तो निकल सकता है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं है। ?लोकतंत्र की असली बेबसी तब दिखती है जब एक शरीफ, ईमानदार और सीधा जनप्रतिनिधि जनता की जायज मांग

प्राइवेटि की नई पहल या सुरक्षा की नई चुनौती?



महेन्द्र तिवारी

आज की डिजिटल दुनिया में जब भी कोई नई सुविधा आती है, तो वह अपने साथ असीम उत्साह और उत्तनी ही गहरी आशंकाएँ लेकर आती है। वर्तमान समय में एक ऐसी ही नई तकनीकी सुविधा को लेकर देश में व्यापक बहस छिड़ गई है। इस नई व्यवस्था के तहत उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए बिना केवल एक विशिष्ट पहचान या गुप्त नाम के माध्यम से दूसरों से बातचीत कर सकेंगे। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को अपनी बेहद निजी और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन विकल्प देना है। दूसरी ओर, सरकार और कानून

दुरुपयोग को लेकर है। यदि कोई शांतिर व्यक्ति किसी प्रसिद्ध बैंक, प्रतिष्ठित सरकारी संस्था, बड़े अधिकारी या किसी सार्वजनिक हस्ती से मिलता-जुलता नाम चुन ले, तो सामान्य उपयोगकर्ता आसानी से भ्रमित हो सकता है। साइबर अपराधी इसी भ्रम और मानवीय विश्वास का अनुचित फायदा उठाकर लोगों से पैसे ठग सकते हैं, उनकी बेहद निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं या फर्जी संदेश फैलाकर समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि देश में फिशिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश धोखाधड़ी और पहचान बदलकर की जाने वाली ठगी के मामलों में 300 प्रतिशत से भी अधिक की तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इन्हीं बढ़ते जोखिमों को देखते हुए सरकार ने संबंधित तकनीकी कंपनी से एक विकसृत और स्पष्ट जवाब मांगा है। अधिकारियों का फर्ज है कि बाजार में इस सुविधा को पूरी तरह लागू करने से पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि किसी अपराधी ने किसी

अन्य व्यक्ति या संस्था की पहचान अपनाने की कोशिश की, तो उसे तकनीकी रूप से कैसे रोका जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताया आवश्यक होगा कि किसी पीड़ित उपयोगकर्ता द्वारा शिकायत मिलने पर कंपनी की ओर से कार्रवाई कितनी तेजी से होगी। जब तक इन सुरक्षा मानकों पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक देश के करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। दूसरी तरफ, तकनीकी कंपनी ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा है कि इस नई सुविधा का उद्देश्य किसी भी अपराधी को वास्तविक पहचान को छिपाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद केवल मोबाइल नंबर की गोपनीयता को एक नया स्तर प्रदान करना है। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी नए ग्राहक, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी या किसी अस्थायी संपर्क से बात करनी पड़ती है। ये लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से अपना निजी मोबाइल नंबर उनके साथ साझा नहीं करना चाहते।

लेकर जाता है और अफसर उसे फाइलों के चक्कर में दौड़ाता रहता है। यह उस जनता का अपमान है जिसने उस प्रतिनिधि को चुना है।

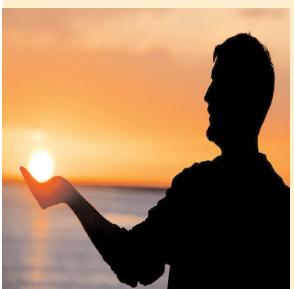
चुनाव में वोट मांगने नेता जाता है, अफसर नहीं। अगर सड़क नहीं बनी, तो जनता नेता को कोसेंगी। अफसर एसी कमरे में बैठकर अगली पोस्टिंग की प्लानिंग कर रहा होता है। जब तक अफसरों की सीधी जवाबदेही जनता या जनप्रतिनिधियों के प्रति सख्त नहीं होगी, तब तक वे खुद को 'माई-बाप' और जनता को 'प्रजा' समझते रहेंगे। यह औपनिवेशिक मानसिकता का बचा हुआ हिस्सा है। संविधान के अनुसार, 'हम भारत के लोग' सर्वोच्च नारा है। जनता ने अपनी ताकत जनप्रतिनिधि को दी है। इसलिए सिद्धांत रूप में चुनी हुई सरकार ही हर हालात में नौकरशाही से ऊपर होनी चाहिए. दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और यह लोकतंत्र की सफलता है. अगर कोई अफसर किसी सांसद या विधायक की बात नहीं सुन रहा है, तो वह वास्तव में उस क्षेत्र की लाखों की आबादी का अनादर कर रहा है। जब अफसरशाही इतनी हावी हो जाए कि राजनेता लाचार हो जाएँ, तो यह 'सच्चे लोकतंत्र' का पतन है और एक 'लूटतंत्र' या 'अफसरतंत्र' की शुरुआत है।

इस व्यवस्था को बदलने के लिए केवल 'दबंग' नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे जागरूक और शिक्षित जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो अफसर की आंखों में आंखें डालकर नियमों के तहत अपना हक मांग सकें और जनता के प्रति

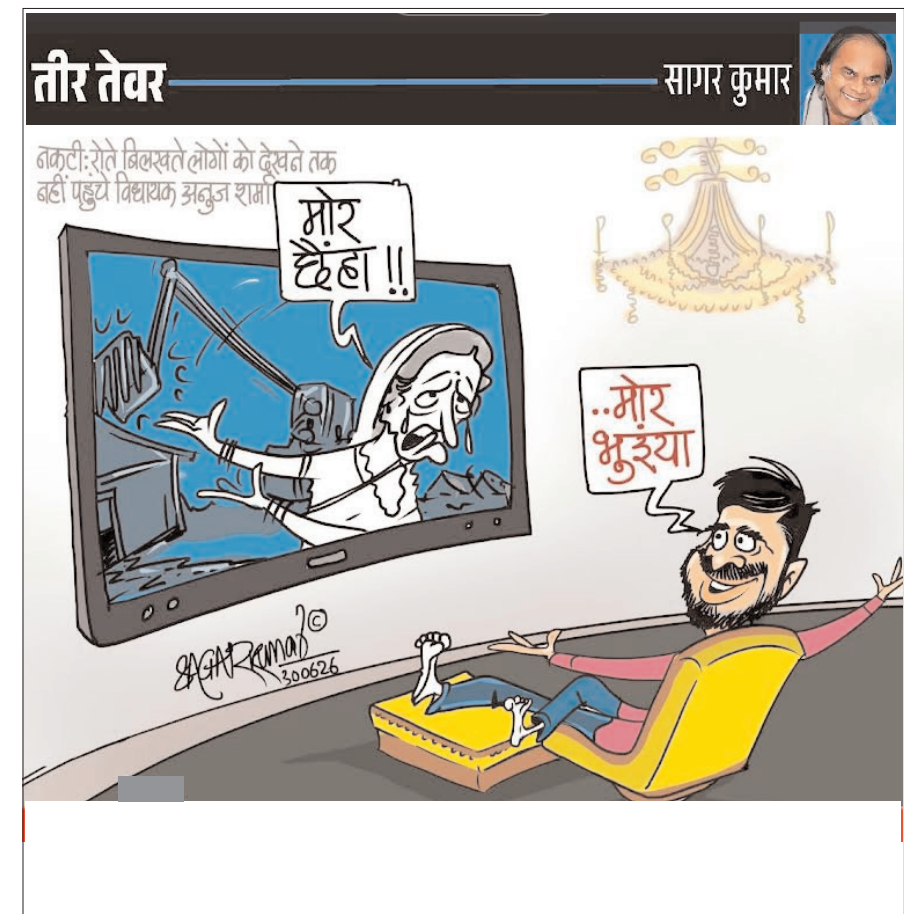
अपनी जवाबदेही को सर्वोपरि रखें। अक्षरों को नियंत्रित करने का अधिकार मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होता है इनको हिम्मत के साथ अफसर को बेअदबी दिखाने पर फटकारने का काम करना चाहिए.अगर वह मनमानी करते हैं, तो उनको फ़ौरन इधर से उधर स्थानांतरित करते रहना चाहिए, ताकि उनकी अकड़ कुछ कम हो. आजादी के बाद देश की जनता को लगा था कि अब उनका राज आ गया है लेकिन पिछले सात-आठ दशकों में हालात यह है अफसर ही राज कर रहे हैं. हालांकि कभी -कभार जब भ्रष्टाचार में लिस अफसर बर्खास्त किए जाते हैं, तब लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है. लेकिन ऐसी सुखद अवसर बहुत कम आते हैं और लंबी पारी खेल कर तमाम आईएएस, आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त हो जाते हैं. और मजे की बात यह है कि कुछ तो सेवानिवृत्त होने के बावजूद किसी न किसी मलाईदार सरकारी आयोग, मंडल, परिषद, अकादमी आदि लें शीर्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पा जाते हैं, और लंबी पारी खेल कर तमाम सामाजिक प्रतिभाओं के साथ अन्याय है जो उनकी जगह नियुक्त किया जा सकते थे. अब समय आ गया है कि ब्यूरोक्रेसी को कसने के लिए एक नागरिक समिति बने, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त रहे. वह समय समय पर ब्यूरोक्रेसी को न केवल फटकारे वर्ग वरन उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री तक अनुशंसा भी करे. ऐसे ही सुधारात्मक पहल से ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित किया जा सकता है।

बोध कथा

मैंने वो चीज पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता



2 दिन किताबों से मन बहल गया फिर वो खोझने लगा।। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। जैसे-जैसे दिन बीतने लगे उसे एक-एक घंटे युगों से लगने लगे। वो चीखता-चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को नहीं बुलाना। वह अपने बाल नोचता, रोंता, गालियां देता, तड़प जाता, मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। परंतु वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता। कुछ दिन बीता धीरे-धीरे उसके भीतर एक अजीब शक्ति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वह बस मौन बैठा रहता। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि एक माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है।



व्यंग्य केसरी

या वैवाहिक आत्मसमर्पण ?



पर ऐसी गंभीरता, जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीतने जा रहा हो। देखने वाले भी वाह-वाह करते हैं—‘देखो, कैसा वीर लग रहा है!’ लेकिन किसी ने आज तक यह नहीं पूछा कि भाई साहब, इस तलवार का उपयोग करना भी आता है या यह सिर्फ फोटो खिंचवाने का सामान है ? तलवार देखकर ऐसा लगता है कि यदि रास्ते में कोई राक्षस मिल गया तो दूल्हा एक ही वार में उसका अंत कर देगा। पर वास्तविकता यह है कि अगर थोड़ा थोड़ा तेज चल पड़े या पटाखा फूट जाए, तो सबसे पहले दूल्हे का संतुलन बिगड़ता है रहती है। उसके बाद दूल्हे का सबसे बड़ा हथियार केवल एक वाक्य रह जाता है— ‘जी, जैसा आप कहें।’ अगर सचमुच तलवार का कोई आधुनिक उपयोग ढूँढ़ना हो, तो उसे केवल शादी के कैंडल, रिबन काटने या सेल्फी में शान बढ़ाने तक

इतिहास

3 जुलाई का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, आविष्कारों और ऐतिहासिक बदलावों के लिए जाना जाता है। आज के दिन विश्व स्तर पर कई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ घटीं, जो इस प्रकार हैं:1608: सैम्युअल डी चम्पलैन (Samuel de Champlain) ने क्यूबेक शहर (Quebec City) की स्थापना की, जो कनाडा में पहला स्थायी यूरोपीय आधार बना।1844: आइसलैंड के टट पर अंतिम ज्ञात ग्रेट ऑक (Great Auks - ना उड़ने वाले पक्षी) को मार दिया गया था, जिसके बाद यह प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई।1863: अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान तीन दिनों तक चला ‘गेटिसबर्ग का युद्ध’ (Battle of Gettysburg) समाप्त हो गया। इसे गृह युद्ध का सबसे खूनी और महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।1962: अल्जीरिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके साथ ही अल्जीरिया के 132 वर्षों के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया।

उच्च न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, जगदलपुर के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को विशेष न्यायाधीश (एनआईए) जगदलपुर बनाया गया है। बलौदाबाजार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (विजिलेंस) नियुक्त किया गया है। वहीं, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेट्री के सचिव ओम प्रकाश जायसवाल को रजिस्ट्रार (न्यायिक) का दायित्व सौंपा गया है। सूरजपुर की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनिता

वारनेर का तबादला बलौदाबाजार किया गया है, जबकि सूरजपुर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थामस एक्का को सूरजपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर को रायपुर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, राकेश कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में अतिरिक्त निदेशक, रूपनारायण पात्रे को हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेट्री का सचिव तथा अमित कुमार कोहली को बलरामपुर-रामानुजगंज पदस्थ किया गया है। अन्य कई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के भी विभिन्न जिलों में तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सभी तबादला जायसवाल को रजिस्ट्रार (न्यायिक) का दायित्व सौंपा गया है। सूरजपुर की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनिता

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पर सख्ती

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बलौदाबाजार में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री वर्मा ने कहा कि खेल मैदान, निस्तारी भूमि और अन्य सार्वजनिक उपयोग की शासकीय जमीनों का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से स्वयं अतिक्रमण नहीं करने और दूसरों को भी

इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अधिकार नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों के पास है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। मंत्री ने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित होता है, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है और निस्तारी संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। राजस्व मंत्री ने दोहराया कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को सुरक्षित रखना भविष्य की पीढ़ियों के हित में आवश्यक है।

मैनपाट में खदान परियोजना पर बवाल: जनसुनवाई का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार

विश्व केसरी■
सरगुजा। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में प्रस्तावित खदान परियोजना को लेकर शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई भारी विरोध और हंगामे के बीच संपन्न हुई। सरभंजा में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परियोजना का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लगातार हो रही बारिश के बावजूद ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सीएमडीसी भागे के नारे लगाए।

ग्रामीणों का कहना है कि खदान परियोजना से क्षेत्र के जंगल, जल स्रोत, खेती और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि परियोजना से स्थानीय लोगों के जीवन और आजीविका पर संकट खड़ा होगा। इसी कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई स्थल पर पहुंचे और परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।



खदान परियोजना को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसे स्थानीय हितों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खदान परियोजना को लेकर जिस स्वीकृति की बात हो रही है, वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दी गई थी। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की भावनाओं और उनकी चिंताओं को

उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए सीमांकन का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुनर्वास की मांग



विश्व केसरी■
सूरजपुर। जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में शुक्रवार को उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए आवंटित शासकीय भूमि के सीमांकन के दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व एवं प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ सीमांकन करने पहुंची तो वर्षों से भूमि पर खेती कर रहे और मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई। स्थिति को देखते हुए मौके

पर पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रशासन के अनुसार मदनपुर और करवा गांव को लगभग 80 एकड़ शासकीय भूमि उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए पहले ही शासन द्वारा आवंटित की जा चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मदनपुर की करीब 35 से 36 एकड़ भूमि का सीमांकन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि

फिलहाल केवल सीमांकन की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे महाविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक ब्लॉक, छात्र-छात्राओं के छात्रावास, ऑडिटोरियम तथा प्रयोगात्मक खेती के लिए भूमि का निर्धारण किया जा सके। दूसरी ओर ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सीमांकन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में सीमांकन

करना उचित नहीं है। जिन परिवारों के मकान और खेती प्रभावित हो रही है, उनके पुनर्वास एवं विस्थापन की स्पष्ट व्यवस्था पहले की जानी चाहिए। ग्रामीणों का दावा है कि कई परिवार वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और कुछ के प्रधानमंत्री आवास भी इसी जमीन पर बने हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि कई परिवारों के पास आजीविका के लिए अन्य कोई जमीन नहीं है। विरोध कर रहे लोगों ने यह भी कहा कि मामला न्यायालय में विचारार्थ है। हाल ही में दूसरे गांव में सीमांकन के बाद हुई कार्रवाई को देखते हुए लोगों में आशंका है कि भविष्य में उनके मकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि पूरी प्रक्रिया राजस्व अभिलेखों और शासन के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है और मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। लंबे समय तक चली समझाइश के बाद पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन का कार्य शांतिपूर्वक जारी रखा गया।

कुत्तों से बचने गांव पहुंचा जंगली हिरण, ग्रामीणों की सतर्कता से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू



खैरागढ़। जिले के ग्राम अवेली में एक जंगली हिरण के गांव में पहुंचने से ग्रामीणों में उत्सुकता का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ आवारा कुत्ते हिरण का पीछा कर रहे थे। जान बचाने के प्रयास में हिरण गांव में घुस आया और एक किसान के ब्यारा में जाकर छिप गया। किसान की नजर हिरण पर पड़ते ही उसने तत्काल कुत्तों को वहां से भगाया। इसके बाद अन्य ग्रामीणों की मदद से हिरण को सुरक्षित पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया, ताकि घबराहट में वह इधर-उधर भागकर घायल न हो। घटना की सूचना तुरंत डायल-112 और वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की मौके पर पहुंची और हिरण का सुरक्षित रेस्क्यू किया। आवश्यक जांच के बाद उसे

प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इस दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग हिरण को देखने के लिए एकत्र हो गए। खैरागढ़ के डीएफओ पंकज राजपूत ने बताया कि जंगली हिरण अक्सर चारा और पानी की तलाश में अथवा आवारा कुत्तों के पीछा करने के कारण जंगल से भटककर गांवों में पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं और तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके। वन विभाग ने ग्रामीणों की सतर्कता और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि समय पर सूचना मिलने से हिरण को सुरक्षित बचाया जा सका।

21 साल बाद पीडिया में फिर गूंजी स्कूल की घंटी, 11 स्कूलों में लौटी पढ़ाई

विश्व केसरी■
बीजापुर। बीजापुर जिले के अतिरसवेदनशोल और पूर्व नक्सल प्रभावित पीडिया क्षेत्र में 21 वर्षों बाद शिक्षा की नई शुरुआत हुई है। वर्ष 2005 में नक्सली हिंसा और सलवा जुद्ध के दौर में बंद हुए 11 शासकीय स्कूलों के दरवाजे नए शिक्षा सत्र के साथ फिर से खुल गए हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। 539 बच्चों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षा की मुख्धारा में



कदम रखा। स्कूल खुलने के अवसर पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया तथा उन्हें स्कूल बैग, कॉपियां और पेन वितरित किए। वर्षों बाद स्कूलों में बच्चों की चहल-पहल

लेौटने से ग्रामीणों ने भी खुशी जताई। कभी माओवादी गतिविधियों के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह उप हो गई थी, जिससे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ था। जिला प्रशासन के प्रयासों

एमसीबी में 2.60 करोड़ की सड़क पहली बारिश में ध्वस्त, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

विश्व केसरी■
एमसीबी। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के बीचों-बीच लंबी दरारें पड़ने और धंसने की घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ग्राम पंचायत मेंड्रा का है, जहां लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन महज दो दिन की हल्की बारिश के बाद ही सड़क कई स्थानों पर फट गई। सड़क के दोनों किनारों पर करीब 50 मीटर तक लंबी और

गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गईं। सबसे गंभीर आरोप पुलिसिया निर्माण को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में दो से तीन किलोमीटर के दायरे से आने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए जहां मजबूत सीमेंटेड पुलिसिया की आवश्यकता थी, वहां कथित तौर पर केवल एक छोटा ब्रूम पाइप डालकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। पर्याप्त जल निकासी नहीं होने से बारिश का पानी सड़क के नीचे भर गया और दबाव बढ़ने पर सड़क धंस गई। ग्रामीणों का आरोप है कि

अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिसके कारण करोड़ों रुपये की परियोजना पहली बारिश भी नहीं झेल सकी। सड़क की बदहाल स्थिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शिकायत और सड़क की स्थिति की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि निर्माण में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मैनपाट में खदान परियोजना पर बवाल: जनसुनवाई का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार

विश्व केसरी■
सरगुजा। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में प्रस्तावित खदान परियोजना को लेकर शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई भारी विरोध और हंगामे के बीच संपन्न हुई। सरभंजा में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परियोजना का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लगातार हो रही बारिश के बावजूद ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सीएमडीसी भागे के नारे लगाए।

ग्रामीणों का कहना है कि खदान परियोजना से क्षेत्र के जंगल, जल स्रोत, खेती और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि परियोजना से स्थानीय लोगों के जीवन और आजीविका पर संकट खड़ा होगा। इसी कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई स्थल पर पहुंचे और परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

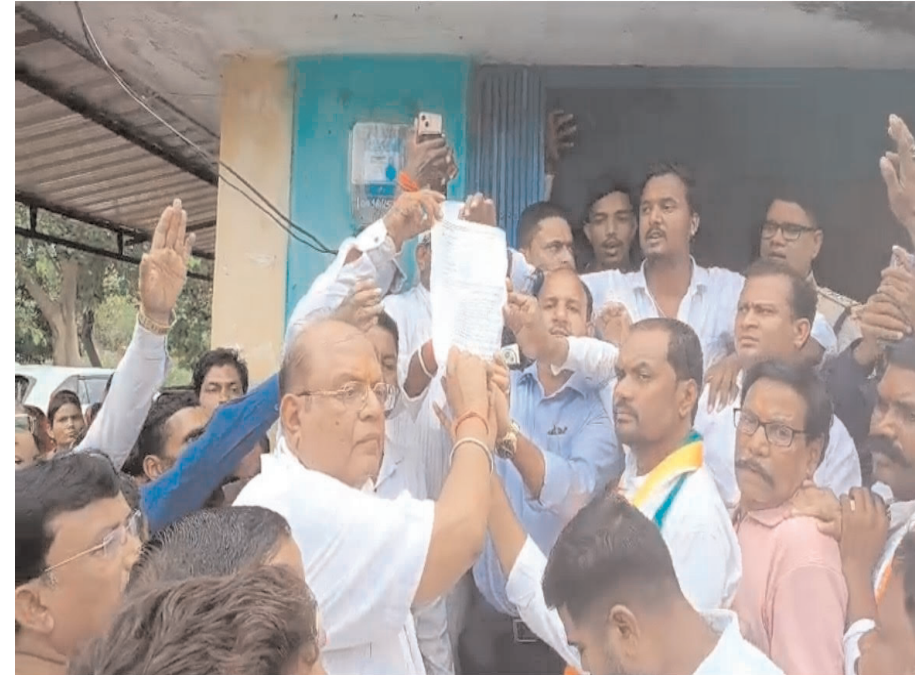


खदान परियोजना को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसे स्थानीय हितों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खदान परियोजना को लेकर जिस स्वीकृति की बात हो रही है, वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दी गई थी। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की भावनाओं और उनकी चिंताओं को

गंभीरता से लेने की बात कही। जनसुनवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी के बीच मैनपाट में खदान परियोजना अब जनआंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। दूसरी ओर, परियोजना को लेकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

कोपरा नगर पंचायत का कांग्रेस ने किया घेराव

विश्व केसरी■
गरियाबंद। जिले के नगर पंचायत कोपरा में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर मनमानी, प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित गड़बड़ी तथा विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, हालांकि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। घेराव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सभा के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण



रैली के रूप में नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का

घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के

नाम 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास

योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विकास कार्यों की जांच, पेयजल व्यवस्था में सुधार, नियमित सफाई, टैक्स वसूली में कथित अनियमितताओं पर रोक तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं से जुड़ी मांगें शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार और नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसी भी अग्रिय स्थिति से निपटने के लिए नगर पंचायत कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा।

पूर्व आईजी सुंदरराज पी बने NIA में आईजी, प्रेस क्लब में दी गई भावमीनी विदाई

विश्व केसरी■
जगदलपुर/बस्तर। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक निर्णायक अभियान का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में आईजी नियुक्त किया है। नई नियुक्ति के बाद उन्होंने बस्तर आईजी का पद छोड़ दिया है और जल्द ही नई जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। सुंदरराज पी के कार्यकाल को बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांति बहाली के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने कई बड़े अभियान चलाए, जिनसे नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता मिली। उनके कार्यकाल के दौरान विकास और सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय



स्थापित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए। वहीं, सुंदरराज पी की रवानगी के साथ ही आईपीएस अधिकारी

बदौनारायण मीणा ने बस्तर के नए आईजी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को

मजबूत बनाए रखने और नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति एवं विकास की दिशा में काम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर

पर बस्तर प्रेस क्लब में पूर्व आईजी सुंदरराज पी के सम्मान में विशेष विदाई एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए आईजी बदौनारायण मीणा, बस्तर कलेक्टर, जिले के प्रसंगी सहित प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। समारोह में स्थानीय पत्रकारों ने सुंदरराज पी के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें बस्तर को नक्सलवाद के खोफ से बाहर निकालने और शांति का माहौल स्थापित करने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में सुंदरराज पी ने बस्तर की जनता, पुलिस बल, प्रशासन और मीडिया का सहयोग मिलने पर आभार व्यक्त किया तथा कहा कि बस्तर से उनका भवनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में बेहतर कार्य करती रहेगी।

कोटवार संघ का एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

विश्व केसरी■
गरियाबंद। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अमलीपदर कोटवार संघ ने शुक्रवार को तहसील मुख्यालय में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोटवारों ने रैली निकालकर शासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अमलीपदर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटवार संघ ने ज्ञापन में दैनिक वेतन में वृद्धि, सेवा सुरक्षा, नियमित नियुक्ति, बिना जांच के निलंबन पर रोक सहित अन्य लंबित मांगों को प्रमुखता से रखा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कोटवार लंबे समय से शासन-प्रशासन की विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाहन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं और न ही सम्मानजनक पारिश्रमिक। इससे



उनके सामने आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां लगातार बढ़ रही हैं। धरना-प्रदर्शन के दौरान व्यापक किया जाएगा। तहसीलदार अमलीपदर ने कोटवार संघ को ज्ञापन प्राप्त कर उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

लिया गया, तो आंदोलन को जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक और व्यापक किया जाएगा। तहसीलदार अमलीपदर ने कोटवार संघ को ज्ञापन प्राप्त कर उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 262 अंक उछला

विश्व केसरी ■

मुंबई। वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। इस दौरान आईटी, रियल्टी, फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 261.79 अंक यानी 0.34 प्रतिशत चढ़कर 77,763.91 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 50 95.15 अंक यानी 0.39 प्रतिशत बढ़कर 24,270.85 पर पहुंच गया।

दिन के सत्र में सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,502.12 से 0.83 प्रतिशत यानी 650.22 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 78152.34 पर खुला और दिन के कारोबार में यह 655.40 अंकों यानी 0.84 प्रतिशत की उछाल के साथ 78,157.52 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 24,175.70 से 0.82 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,375.65 पर खुला और दिन के

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी रियल्टी सबसे अधिक लाभ कमाने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद निफ्टी हेल्थकेयर (1.8 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (1.7 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (1.7 प्रतिशत) और निफ्टी मेटल (0.7 प्रतिशत) ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके बाद निफ्टी एनर्जी (-1.30 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (-0.4 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (-0.4 प्रतिशत), निफ्टी कंप्यूटर इयूरेबल्स (-0.3 प्रतिशत) और निफ्टी बैंक (-0.16 प्रतिशत) का स्थान रहा।

निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मैक्स हेल्थकेयर, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लैब्स, बजाज फिनसर्व, अपोलो होस्पिटल्स और भारती एयरटेल शामिल रहे, जबकि एक्सिस बैंक, एसबीआई, एलएंडटी, बजाज-ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और एनटीपीसी के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 2026 की पहली छमाही में संस्थागत निवेश 50 प्रतिशत बढ़ा

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2026 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 50 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कोलियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद भी देश के रियल एस्टेट ने 2026 की जनवरी-जून अवधि में मजबूत निवेश हासिल किया है और यह सेक्टर का छह वर्षों में सबसे अच्छा पहली छमाही का प्रदर्शन है।

रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल-जून तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश सालाना आधार पर 70 प्रतिशत बढ़कर 2.9 अरब डॉलर हो गया है।

घरेलू निवेशकों ने 2.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ बाजार में बढ़त बनाए रखी, जो कुल निवेश का 57 प्रतिशत था, जबकि विदेशी निवेश सालाना आधार पर 24

इस तरह, इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लगातार चौथे सप्ताह बढ़त का सिलसिला जारी रहा।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप में 0.19 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

भारत की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2032 तक तीन गुना बढ़कर 100 गीगावाट होने की उम्मीद : रिपोर्ट



विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2032 तक बढ़कर 100 गीगावाट हो सकती है, जो कि 2025 में 32 गीगावाट है। साथ ही स्थापित एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की क्षमता 10 गुना से अधिक बढ़कर 31 गीगावाट-घंटा होने की उम्मीद है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस की रिपोर्ट में इस तेज वृद्धि का श्रेय कंपनियों के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों, आसमान छूते ग्रिड टैरिफ और ऊर्जा लचीलेपन की बढ़ती आवश्यकता को दिया गया है, जिसमें राज्य-स्तरीय नियामक इनोवेशन स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति को तेज कर रहा है।

यह रिपोर्ट नई दिल्ली की

एनर्जी ट्रांजिशन (स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव) को तेजी देने के लिए ऐसे समाधान निकालना है जिन्हें असल में लागू किया जा सके।

आईईएसडब्ल्यू के अध्यक्ष देबमाल्य सेन ने कहा, 'हमारी नई रिसर्च से पता चलता है कि भारत का सोएंडआई (कमर्शियल और इंडस्ट्रियल) एनर्जी स्टोरेज मार्केट न सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि एक नए दौर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्यों की दूरदर्शी नीतियों और कॉर्पोरेट जगत से बढ़ती मांग के कारण, स्टोरेज अब सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि मजबूती और डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक अहम रणनीतिक टूल बनता जा रहा है। अभी जो तेजी दिख रही है, वही अगले दशक में इस सेक्टर की दिशा तय करेगी।'

रिपोर्ट में महाराष्ट्र की नई रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज पॉलिसी पर जोर दिया गया है, जिसके तहत 100 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले हर नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए स्टोरेज की सुविधा जरूरी है। इस पॉलिसी के अनुसार, डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को भी वित्त वर्ष 2035-36 तक अपनी कुल बिजली का 10 प्रतिशत हिस्सा स्टोरेज से हासिल करना होगा।

गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान भी कॉस्ट-रिफ्लेक्टिव बैंकिंग, सेटलमेंट पॉलिसी और ट्रांसमिशन चार्ज में छूट जैसे उपायों के जरिए इसे तेजी से अपनाने में मदद कर रहे हैं।

कमजोर डॉलर से सोने और चांदी में तेजी, एक प्रतिशत से ज्यादा उछली कीमतें

विश्व केसरी ■

मुंबई। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार के कारोबार में तेजी देखी जा रही है। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 4,300 रुपए तक बढ़ गया है।

मल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,45,758 रुपए के मुकाबले 2,082 रुपए या 1.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,47,840 रुपए पर खुला।

सुबह 9:48 पर यह 2,102 रुपए या 1.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,47,860 रुपए पर था।

सोने ने अब तक के कारोबार में 1,47,375 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,47,977 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

चांदी में भी तेजी देखी जा रही है। चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,33,304 के मुताबले 3,191 रुपए या 1.36 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली 2,36,495 रुपए पर खुला।

खबर लिखे जाने तक यह 4,251 रुपए या 1.82 प्रतिशत की



तेजी के साथ 2,37,555 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,36,495 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,38,216 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,191 डॉलर प्रति औंस और चांदी 3.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.93 डॉलर प्रति औंस पर था।

जानकारों के मुताबिक, सोने में गिरावट की वजह डॉलर इंडेक्स में

कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतें नीचे आने के कारण महंगाई बढ़ने की संभावना कम होना है।

डॉलर इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है और यह घटकर 100.56 पर आ गया है, जो कि पहले 101 के ऊपर था।

डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं- यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक- के मुकाबले स्थिति को दिखाता है।

भारत के कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की आय वृद्धि दर 2030 तक 17.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में वर्ष 2025-2030 की अवधि के दौरान आय 17.3 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

ब्रिकवर्क रेंटिस की रिपोर्ट के अनुसार, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में आय में तेज बढ़ोतरी की वजह क्रेडिट ग्रोथ, जीएसटी में कटौती, टियर-II और टियर-III शहरों से बढ़ी हुई मांग और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर झुकाव है।

वहीं, हेल्थकेयर सर्विस सेक्टर के लिए अच्छे संकेतकों में मजबूत रुचि और डेट कवरेज रेश्यो, लगभग 13 अरब डॉलर का मेडिकल टूरिज्म मार्केट और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम का विस्तार शामिल है।

ब्रिकवर्क रेंटेंस के रिसर्च हेड राजीव शरण ने कहा, 'हमें उम्मीद



है कि वित्त वर्ष 26 में मजबूत मैनुफैक्चरिंग और सर्विस गतिविधियों के दम पर जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत बनी रहेगी। वित्त वर्ष 27 के लिए वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 27 में महंगाई दर लगभग 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, हालांकि, भू-राजनीतिक जोखिम और अल नौनो पर नजर रखना जरूरी है।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 27 में अपने 25 रेटेड सेक्टरों में से 22 के लिए स्थिर क्रेडिट आउटलुक का अनुमान लगाया गया है। इसे मजबूत घरेलू मांग, सरकार के लगातार कैपिटल

खर्च, अच्छी बैलेंस शीट, बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बावजूद अनुमानित कैश फ्लो का समर्थन मिला है।

टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लांजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल और पावर जेनरेशन सेक्टर को डी-लीवरेजिंग (कर्ज कम करने), पॉलिसी सपोर्ट, नए टेड एपीमेंट के तहत निर्यात के मौकों और लंबे समय तक मांग की संभावनाओं से फायदा मिलता है।

ब्रिकवर्क रेंटेंस के चीफ रेंटेंस ऑफिसर, के. एच. पटनायक ने कहा, 'हालांकि केमिकल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर मार्जिन के दबाव का सामना कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट व एयरपोर्ट पर अभी भी काफी कर्ज है, फिर भी उनकी क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत सॉल्वेंसी, बेहतर होती प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क रेवेन्यू की संभावनाओं से समर्थित है।

जून में भी भारत को सबसे अधिक एलपीजी सप्लाई करने वाला देश बना अमेरिका

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। अमेरिका जून में भी भारत को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की सबसे बड़ी आपूर्ति करने वाला देश बना रहा। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने पारंपरिक खाड़ी देशों पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है।

कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत ने अमेरिका से 7.73 लाख मीट्रिक टन (773.78 टीएमटी) एलपीजी आयात की, जो मई की तुलना में 19.4 प्रतिशत अधिक है। वहीं, जून के दौरान भारत का कुल एलपीजी आयात 3 प्रतिशत बढ़कर 11.91 लाख मीट्रिक टन (1,191 टीएमटी) हो गया, जबकि मई में यह 11.55 लाख मीट्रिक टन (1,155 टीएमटी) था।



जून में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता रहा, जहां से आयात 16.6 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, जो मई में 1.34 लाख मीट्रिक टन था। वहीं, सऊदी अरब और कुवैत ने जून में भारत को 64-64 हजार मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की। अमेरिका से एलपीजी आयात में लगातार बढ़ोतरी भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष के बाद ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाया जा रहा है। इसी दिशा में सरकारी तेल

रिफाइनरियों ने 2026 से अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात करने के लिए दीर्घकालिक समझौता भी किया है, जिससे भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग और मजबूत होगा तथा खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

उद्योग से जुड़े स्रोतों के अनुसार, भारत ने अगस्त तक के लिए कच्चे तेल और एलपीजी दोनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुलने के बाद खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने लगी है, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता को लेकर बनी चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं।

महाराष्ट्र को बायोप्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, 25000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य

विश्व केसरी ■

मुंबई। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने और महाराष्ट्र को हरित विनिर्माण (ग्रीन मैनुफैक्चरिंग) का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महागुति सरकार ने 'महाराष्ट्र बायोप्लास्टिक्स पॉलिसी-2026' को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत बायोप्लास्टिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव) और विशेष वित्तीय सहायता का व्यापक पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

यह नीति वर्ष 2026 से 2031 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का



लक्ष्य महाराष्ट्र को बायोप्लास्टिक्स के उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार और निर्यात का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। सरकार को उम्मीद है कि इस

पहल से 25,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, 1.31 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और 30,039 करोड़ रुपये के राजस्व का सृजन होगा।

नीति के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख टन पीएलए (पॉलीलैक्टिक एसिड) और अन्य बायोपॉलिमर उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राज्य की अयातिता पीएलए पर निर्भरता में 50 प्रतिशत की कमी लाने की योजना है।

सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों में सिंगल-यूज प्लास्टिक के 30

प्रतिशत उपयोग को कम्पोस्टेबल विकल्पों से बदलने, 1 अरब डॉलर के निर्यात और 1 लाख किसानों को बायोप्लास्टिक्स वैल्यू चेन से जोड़ने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति के लिए 10,892 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। इसमें पहले पांच वर्षों के दौरान 782 करोड़ रुपये तथा अगले 20 वर्षों में 10,110 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2026 में घूमने के लिए सबसे सस्ते हैं ये 6 देश, भारतीयों के बजट में होगी इंटरनेशनल ट्रिप!



दुनिया में ऐसे कई खूबसूरत जगह हैं, जहां भारतीय पर्यटक कम खर्च में शानदार छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 6 देशों के बारे में, जो भारतीय यात्रियों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं।

अगर आप 2026 में विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट की चिंता आपको रोक रही है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

दुनिया में ऐसे कई खूबसूरत देश हैं जहां भारतीय पर्यटक बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना शानदार छुट्टियां बिता सकते हैं। इन देशों में रहने, खाने और घूमने-फिरने का खर्च काफी कम है। आइए, ऐसे ही 6 बजट-फ्रेंडली देशों के बारे में जानते हैं...

2026 में घूमने के लिए सबसे सस्ते हैं ये 6 देश-

वियतनाम
वियतनाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और सस्ते सफ़र के लिए जाना जाता है। हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और हा लॉन्ग बे जैसी जगहें कम बजट में शानदार अनुभव देती हैं।

नेपाल
भारत का पड़ोसी देश नेपाल, विदेश घूमने के लिए एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प है। काठमांडू, पोखरा और चितवन नेशनल पार्क जैसी जगहें प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का सही मेल हैं। भारतीय नागरिकों को यहां जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती।

श्रीलंका
समुद्र तटों, पहाड़ों, चाय के बागानों और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर श्रीलंका

भारतीय पर्यटकों के लिए एक सस्ता विदेशी डेस्टिनेशन है। कोलंबो, कैंडी और एला यहां



घूमने की लोकप्रिय जगहों में शामिल हैं।

इंडोनेशिया
बाली के अलावा, इंडोनेशिया में कई खूबसूरत द्वीप हैं जहां कम बजट में छुट्टियों का मजा लिया जा सकता है। यहां के समुद्र तट, मंदिर और स्थानीय संस्कृति पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं।

भूटान
अगर आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और साफ़-सुथरे माहौल का आनंद लेना चाहते हैं, तो भूटान एक शानदार विकल्प है। थिम्पू, पारो और टाईगर नेस्ट मॉनेस्ट्री यहां के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं।

कंबोडिया
कंबोडिया प्राचीन अंकोरवाट मंदिर परिसर, अपने समृद्ध इतिहास और सस्ते सफ़र के लिए मशहूर है। यहां रहने, लोकल ट्रांसपोर्ट और खाने-पीने का खर्च काफी कम है।

से 12 साल के बच्चों की डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड्स, कंप्यूटर से भी तेज दौड़ेगा दिमाग और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर!



अपने 5 से 12 साल के बच्चों को दें सुपरफूड्स की ताकत! सही डाइट से उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ेगा और बीमारियां उनसे कोसों दूर रहेंगी। इन खास फूड्स को उनकी डाइट में शामिल कर आप उन्हें स्वस्थ और बुद्धिमान बना सकते हैं। जानिए कौन से हैं वे सुपरफूड्स जो आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं...

5 से 12 साल की उम्र बच्चों के शरीर और दिमाग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसी समय बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां विकसित होती हैं, और दिमाग सीखने की क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। इस उम्र में दिया गया सही पोषण बच्चे के पूरे जीवन की सेहत और मानसिक क्षमता की नींव रखता है। लेकिन आज के समय में बच्चों की खाने की आदतों में जंक फूड शामिल हो गया है, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस उम्र में बच्चों की डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि उनका विकास सही दिशा में हो सके। आइए जानते हैं 5 से 12 साल के बच्चों की डाइट में क्या होनी चाहिए...

सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की बच्चों के शरीर को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की होती है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं को बनाने और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। अगर बच्चे की डाइट में दालें, दूध, दही, पनीर, अंडा, सोया, चना या चिकन जैसे स्रोत शामिल किए जाएं, तो उनका शारीरिक विकास बेहतर तरीके से होता है।

मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बेस्ट है सेल्फ-वैलिडेशन का ये फार्मूला, अंदर से बनेंगे लोहे सा मजबूत, छू नहीं पाएगा स्ट्रेस



क्या दूसरों की बातें और तनाव आपकी मानसिक शांति को बिगाड़ देते हैं? जानिए खुद को अंदर से लोहे जैसा मजबूत और 'मेंटली अनटचेबल' बनाने का यह खास सेल्फ-वैलिडेशन फार्मूला, जिससे कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी।

लगातार बढ़ता कम्पटीशन, लोगों की आलोचनाएं और मानसिक दबाव के बीच खुद को शांत और इमोशनली स्टेबल रखना बेहद मुश्किल हो गया है। अक्सर लोग दूसरों के कड़वे बयानों, तनावपूर्ण स्थितियों या अचानक आने वाली असफलताओं के कारण अंदर से टूट जाते हैं। ऐसे में खुद को 'मेंटली अनटचेबल' यानी मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि कोई आपको ठेस न पहुंचा सके, बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह

है परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीखें।

नियम 1: हालातों को नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलें जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन उन पर हम कैसा रिएक्ट करते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गुस्से या बिना सोचे-समझे दी गई प्रतिक्रिया सिर्फ नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। इसलिए, किसी भी चुनौती के सामने आने पर वे तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं और फिर सोच-समझकर जवाब देते हैं। यह छोटी सी आदत आपके मानसिक तनाव को आधा कर देती है।

नियम 2: खुद पर रखें अटूट

विश्वास दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला है एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना जिसे कोई हिला न सके, जब आपको अपनी क्षमताओं, अपनी मेहनत और अपने फैसलों पर पूरा भरोसा होता है, तो दूसरों की राय या आलोचनाएं आपके इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचा पातीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर वक्त दूसरों से 'सेल्फ-वैलिडेशन' या तारीफ की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वे अपने खुद के काम से संतुष्ट होते हैं। वे शांति से अपनी कमियों पर काम करते हैं और अपनी ताकतों को और मजबूत बनाते हैं।

नियम 3: अपनी एनर्जी बचाएं और बाउंड्रीज तय करें

हर बात या हर परिस्थिति आपको मानसिक ऊर्जा और समय की हकदार नहीं होती।



फूड बारिश के मौसम में बनाइए ये खास तरह के लड्डू, स्वाद और सेहत दोनों का है भंडार, जानिये तरीका



बारिश में मेथी-गुड़, तिल-गुड़, सूखे मेवे, नारियल और आटे-गुड़ के लड्डू इम्प्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, पर कैलोरी का ध्यान रखें। तो आप इस तरह के लड्डू बनाकर अपनी सेहत को लगातार स्वस्थ बनाएं रख सकते हैं।

बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी फुहारें और सुहाना माहौल लेकर आता है। इस मौसम में अक्सर कुछ गर्मीगर्म और पौष्टिक खाने का मन करता है। ऐसे में लड्डू एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि कुछ पारंपरिक लड्डू बारिश के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में भी मदद कर सकते हैं।

मेथी और गुड़ के लड्डू
मेथी और गुड़ से बने लड्डू मानसून के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। मेथी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को मजबूती देते हैं, जबकि गुड़ आयरन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। इन लड्डूओं का सेवन सीमित मात्रा में करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान भी कम महसूस होती है।

तिल और गुड़ के लड्डू
तिल के लड्डू सर्दियों में ही नहीं, बारिश के मौसम में भी अच्छे माने जाते हैं। तिल में कैल्शियम, प्रोटीन और स्वस्थ वसा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वहीं गुड़ शरीर को प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा देता है।

बारिश के मौसम में न करें खानपान की गलती! ये सब्जियां बनेंगी सेहत की प्राकृतिक ढाल



बरसात के मौसम में नमी बढ़ने से फंगल इंफेक्शन, कमजोर पाचन और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे समय में खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार लौकी,

तोरी, परवल, करेला, भिंडी और टिंडा जैसी मौसमी सब्जियां भोजन में शामिल करनी चाहिए। ये सब्जियां हल्की होती हैं, आसानी से पच जाती हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं।

संतुलित आहार के साथ स्वच्छता का ध्यान रखने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है और संक्रमण का जोखिम कम हो सकता है। बरसात में ताजी और अच्छी तरह पकी हुई सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए

अधिक लाभकारी माना जाता है। बरसात के दिनों में ज्यादातर फसलों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगता है।खासकर पत्तेदार सब्जियों और मशरूम की तरह नमी में ही उगने वाली सब्जियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।इसके अलावे अरबी, बैंगन, फूलगोभी इत्यादि कुछ ऐसी सब्जियां हैं, जिनका सेवन भी बरसात में उचित नहीं माना जाता है।

हालांकि ठीक इनके विपरीत कुछ हरी सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनका सेवन मौनसून में भी स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। करीब 40 वर्षों से आयुर्वेदाचार्य के रूप में कार्य कर रहे बेतिया के आचार्य भुवनेश पांडे ने इन्हीं खास सब्जियों पर कुछ विशेष जानकारी साझा की है।

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है करेले का।आचार्य बताते हैं कि बरसात में करेले का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। यह शरीर की विषाक्ता को कम करता है, साथ ही खून की गंदगी को भी साफ करता है। स्वाद में कड़वा होने के बावजूद करेले के पोषण और

चिकित्सकीय गुण आपको स्वस्थ रहने और मानसून की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। इसका स्वाद मीठा और गुण ठंडक देने वाला होता है। कब्ज, गैस और पाचन से जुड़ी

जा सकता है।इसमें न तो कीड़े लगने का डर होता है और न ही सड़ने का। हरी और पौष्टिक गुणों से भरपूर होने की वजह से इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है.हां, इसे खरीदते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो ताजी और नाजुक हो.

खीरा, कद्दू और तोरी का सेवन भी बरसात में किया जा सकता है.एक्सपर्ट्स बताते हैं तोरी कफ और पित्त नाशक के साथ भूख बढ़ाने वाली सब्जी है.त्वचा के रोग, एनीमिया और सूजन वाले लोगों के लिए यह किसी औषधि से कम नहीं है.इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया को कम करता है।

खीरा को गर्मियों का सुपर फूड कहा जाता है. यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ पाचन में सुधार और वजन को नियंत्रित करता है. बरसात में जहां ज्यादातर सब्जियों में फंगस और विषाक्ता जैसी समस्या दिखने लगती है, वहीं खीरा इन सभी समस्याओं से बचा रहता है।

जापानी मीडिया ने 16वें भारत-जापान समिट की सफलता की सराहना की, गहरे होते रणनीतिक संबंधों पर दिया जोर

विश्व केसरी ■	
टोक्यो। कई जापानी अखबारों और मीडिया आउटलेट्स ने नई दिल्ली में हुए सफल 16वें भारत-जापान वार्षिक समिट को सकारात्मक कवरेज की है। इसमें कई रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में लगातार हो रही तरक्की पर जोर दिया गया है।	
यह कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी समकक्ष साने ताकाइची के बीच गुरुवार को 16वीं भारत-जापान वार्षिक समिट बातचीत के बाद आया। इस समिट के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और उसे मजबूत किया। द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताई चैन इशू, ऊर्जा सुरक्षा और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, गुरुवार को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची ने जापान के एक खास हिंद-प्रशांत साझेदार के साथ संबंध मजबूत करने का कदम उठाया। रिपोर्ट में कहा गया, ‘टोक्यो के लिए यह समिट ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के लगातार आर्थिक फायदे के इस्तेमाल को लेकर बीजिंग के साथ तनाव	



बढ़ रहा है, जिसमें डुअल-यूज वाले सामानों से जुड़े हालिया एक्सपोर्ट कंट्रोल उपाय और जापानी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है। इसमें आगे कहा गया है, ‘ताकाइची सरकार के लिए सप्ताई चैन में मजबूती को एक डिप्लोमैटिक प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए, भारत अपने बड़े बाजार, बढ़ते मैनुफैक्चरिंग बेस और तकनीकी श्रमिकों के बड़े संपर्क को देखते हुए एक आकर्षक साझेदार बन गया है।

क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस इलाके में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बीच, जापान भारत को एक आजाद और खुले हिंद-प्रशांत को आगे बढ़ाने में एक अहम साझेदार मानता है।

रिपोर्ट में बताया गया, ‘यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब चीन-जापान के संबंध अभी भी खराब हैं। जनवरी से, चीन ने जापान जाने वाले सिविलियन और मिलिट्री इस्तेमाल के लिए डुअल-यूज आइटम के शिपमेंट पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है, जिसमें शायद जरूरी रैयर अर्थ्स भी शामिल हैं। पिछले साल नवंबर में ताइवान पर पीएम ताकाइची की बातों से संबंध में तनाव नजर आया और बीजिंग नाराज हो गया था।

प्रधानमंत्री ताकाइची और पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट और चीन में हो रहे विकास के जवाब में ऊर्जा और जरूरी मिनरल्स का सप्ताई सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए आर्थिक सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत जताई।नई दिल्ली में 90 मिनट की बातचीत के दौरान, दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमत हुए और जापान ने भारत को यूनिर्कोन कम्प्यूनिक्शन एंटेना एक्सपोर्ट करने से संबंधित एक बड़ा समझौता किया। द जापान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ये एंटेना अभी जापानी मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के मोगामी-क्लास डिस्ट्रॉयर पर लगे हैं।

बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकाइची ने कहा, ‘भारत एक भरोसेमंद साझेदार है जिसके साथ हमारा रणनीतिक दृष्टिकोण साझा है। हम अपने संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेताओं ने पिछले साल बदले गए जापान और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर ताकाइची की बातों से संबंध में तनाव नजर में सहयोग और बढ़ाने पर सहमत जताई। मंत्रालय ने आगे कहा, ‘उन्होंने यह भी कहा कि सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें हिंद महासागर में ट्रेनिंग को गहरा करना, नेवी के जहाजों के रखरखाव में सहयोग को बढ़ावा देना, और ‘मेक इन इंडिया’ पर आधारित रक्षा उपकरणों और तकनीकों में सहयोग भी शामिल है। उन्होंने ‘यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रैडियो एंटीना ‘यूनिर्कोन’ के ट्रांसपर में हुई प्रगति का स्वागत किया। इस तरह के सहयोग को गहरा करने के लिए, दोनों नेताओं ने संबंधित विभागों को इस साल के अंदर बातचीत करने और अगला जापान-भारत ‘2+2’ करने का निर्देश दिया।

दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास, होनोलूलू पहुंचा भारतीय विमान

विश्व केसरी ■	
नई दिल्ली। नौसेना का लंबी दूरी का समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक पी-8आई विमान अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित होनोलूलू पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का यह विमान यहां दुनिया के सबसे बड़े बहुगुष्टीय समुद्री युद्धाभ्यासों में से एक ‘रिम ऑफ द पैसिफिक’ (रिमपैक) 2026 में हिस्सा लेगा। यह अभ्यास 01 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। अपनी इस भागीदारी से भारतीय नौसेना ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी बढ़ती सामरिक भूमिका का एक और मजबूत संदेश दिया है। भारतीय नौसेना ने इस नैनाती को ‘ब्रिज्रेस ऑफ फ्रेंडशिप’ यानी मित्रता के पुल का प्रतीक बताया है। नौसेना के अनुसार, यह भागीदारी स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। साथ ही, इससे मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी),	

समुद्री क्षेत्र की निगरानी और संचालनात्मक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। पी-8 आई विमान की बात करें तो, यह भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान है। यह लंबी दूरी तक समुद्र में निगरानी करने, दुश्मन की सुरक्षा अभियानों को अंजाम देने और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। इसी कारण यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। वहीं, यह समुद्री अभ्यास ‘रिमपैक’ दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें अनेक देशों की नौसेनाएं भाग लेकर समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जैसे अभियानों का अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा समुद्री डकैती-रोधी अभियान, बारूदी सुरंग निष्क्रियकरण तथा अन्य जटिल समुद्री अभियानों का संयुक्त अभ्यास भी इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वय बढ़ाना और साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित करना है।

रिमपैक 2026 में भारतीय नौसेना की भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय समुद्री सुरक्षा साझेदार के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। इस अभ्यास के माध्यम से भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ आधुनिक युद्धक तकनीकों, सामरिक अनुभवों और संयुक्त अभियानों की क्षमता को और सुदृढ़ करेगी, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। गौरलभ है कि अदन की खाड़ी में बुधवार को ही समुद्री लुटेरों ने एक व्यापारी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय नौसेना की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने इन समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद यहां सही समय पर पहुंचा और संकट में फंसे मालवाहक जहाज एमवी गोलडन आर्सेनल को मदद की।

वयूबा के डिप्लोमैट का दावा-अमेरिका दूसरे देशों पर वयूबा को अलग-थलग करने के लिए डाल रहा है दबाव

हवाना। क्यूबा के उपविदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडोज डी कोसियो के अनुसार, अमेरिकी सरकार दुनिया भर की सरकारों पर क्यूबा के साथ द्विपक्षीय स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम खत्म करने का दबाव बना रही है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, क्यूबा के उपविदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि कार्यक्रमों को खत्म करने का असर यह हुआ है कि कई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से दूर हो गईं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वे अमेरिका द्वारा क्यूबा पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के खिलाफ अपने पारंपरिक रुख में बदलाव करें और यहां तक कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा करने से भी इनकार कर दें। उन्होंने कहा कि क्यूबा को फ्यूल एक्सपोर्ट करने पर

वाशिंगटन के प्रतिबंध का पालन करने के लिए वह पहले से ही दूसरी सरकारों पर दबाव डाल रहा है। क्यूबा के अधिकारियों ने बार-बार वाशिंगटन के ऊर्जा प्रतिबंधों की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और सामूहिक सजा का एक रूप बताया है। क्यबा के अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजाना लंबे समय तक ब्लैकआउट, ट्रांसपोर्ट की कमी और आर्थिक गतिविधियों में रुकावटें आती हैं।क्यूबा ईंधन आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पिछले छह महीनों में क्यूबा को सिर्फ एक ऑयल टैंकर रूसी अनातोली कोलोडकिन मिला, जिसमें लगभग 100,000 टन कच्चा तेल है। आधिकारिक सोर्स के मुताबिक, क्यूबा की सामान्य तरीके से काम करने के लिए हर महीने लगभग आठ फ्यूल टैंकर चाहिए होते हैं।

वेनेजुएला में भूकंप से हुई तबाही के बाद हालात हो रहे सामान्य, प्रभावित इलाके में मेट्रो और रेल सेवाएं हुई बहाल

काराकस। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए भूकंप के बाद धीरे-धीरे हालात स्थिर हो रहे हैं। परिवहन मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, लॉस टेक्स शहर में मास-ट्रांजिट रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही 24 जून को देश में आए भूकंपों के बाद प्रभावित सभी सार्वजनिक परिवहन रेल सेवाएं अब पूरी तरह बहाल हो चुकी हैं। लॉस टेकेस की रेल सेवा संचालन में लौटने वाली आखिरी ट्रांजिट प्रणाली थी।

मंत्रालय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि लॉस टेक्स मेट्रो की सेवाएं भूकंप के बाद रोक दी गई थीं। हालाँकि, इसे फिर से बहाल करने से पहले सर्विस की जांच और निगरानी की गई। बता दें, लॉस टेक्स मेट्रो मिरांडा राज्य की राजधानी को काराकास से जोड़ती है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंत्रालय ने यह भी कहा कि काराकास को मिरांडा राज्य के वैंलेस डेल तुई इलाके से जोड़ने वाला रेलवे

सिस्टम वालेंसिया मेट्रो भी सामान्य तरीके से चल रहा है। वालेंसिया वेनेजुएला के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर को सेवा देने वाला रेल सेवा है।

शक्तिशाली भूकंपों से उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा में सड़कों को बहुत नुकसान हुआ। वहीं, काराकास और वेनेजुएला के मध्य क्षेत्र के अन्य राज्यों में ये नुकसान कम रहा।

जॉर्डन की सशस्त्र सेना ने एक बयान में कहा कि देश ने कतर के सहयोग से गुरुवार को वेनेजुएला में राहत कार्यों में मदद के लिए मानवीय, मेडिकल और खाद्य सहायता भेजी। बयान के मुताबिक, किफ अब्दुल्ला के निर्देशों के तहत, कतर का सी-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अमान से वेनेजुएला की राजधानी काराकस के लिए रवाना हुआ। इसमें चोटों के इलाज के लिए 26 टन खास मेडिकल सप्लाई, साथ ही मेडिकल इस्तेमाल का सामान, उपकरण, जरूरी खाने का सामान और खाने के पार्सल थे।

अमेरिका ने 250वीं सालगिरह के लिए पासपोर्ट किया लॉन्च, रुबियो बोले- ये हमारी विरासत, मूल्यों का प्रतीक

वाशिंगटन। अमेरिका ने अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगार पासपोर्ट पेश किया है, जिसमें एक नए डिजाइन वाला ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी शामिल है। आने वाले महीनों में पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के ज्यादातर हिस्से को डिजिटाइज करने की योजना है। इस विशेष संस्करण के पासपोर्ट पर अमेरिका की स्थापना की याद में विशेष कलाकृतियां (कस्म आर्टवर्क) बनाई गई हैं, जबकि इसमें सामान्य अमेरिकी पासपोर्ट की सभी सुरक्षा विशेषताएं भी बरकरार रखी गई हैं। यह पासपोर्ट 6 जुलाई से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

वाँशिंगटन में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि यह पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि अमेरिका की विरासत, मूल्यों और राष्ट्रीय पहचान का भी

प्रतीक है। विदेश सचिव रुबियो ने कहा, ‘पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है; यह अपने मतलब के हिसाब से बहुत कीमती है। जब हम विदेश जाते हैं तो हममें से कई लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात होती है कि हम वह अमेरिकी पासपोर्ट दिखा सकें।’

उन्होंने कहा कि यह स्मारक ‘मानव इतिहास के सबसे राष्ट्र की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ’ को समर्पित है।

रुबियो ने कहा कि रीडिजाइन किया गया पासपोर्ट अमेरिकी पासपोर्ट कार्यक्रम को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। स्मारक संस्करण से शुरुआत करते हुए, पासपोर्ट को एक विशेष प्रेजेंटेशन बॉक्स में दिया जाएगा, जिसके साथ उसकी प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी) भी शामिल होगा।

रुबियो ने कहा, ‘हमने सोचा



कि अमेरिकी पासपोर्ट जैसी जरूरी और समानाजनक चीज के लिए, इसमें सच में उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए।' उन्होंने भविष्य के अपग्रेड के बारे में भी बताया, जिससे आवेदक लगभग पूरा पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। रुबियो ने कहा, ‘आप असल में ऑनलाइन जा पाएंगे। आप लगभग सारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन कर पाएंगे।’

प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत, आवेदक अपने कंप्यूटर या मोबाइल

भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र कर राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के लिए तय किया नया मानक

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बताया और कहा कि अमेरिका को महंगाई और इंटरनेट रेट की चिंताओं से बंधे रहने के बजाय बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हासिल करना चाहिए।

सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की, जबकि मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को लेकर आलोचना की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘आपके पास कुछ देश हैं, भारत उनमें से एक है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन यह 7, 8 फीसदी पर है। हमें ऊपर बढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं, तो वे इसे खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका को बहुत तेजी से आर्थिक विस्तार का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें 4 फीसदी पर रुकना चाहिए। हमें 12 और 13

फीसदी ज़ोडीपी पर रहना चाहिए। उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी रोजगार डेटा जारी होने के बाद ब्याज दरों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाजार इन दिनों ‘महंगाई के विरोधाभास’ (प्रिंझिपल) से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े आने पर भी निवेशक अक्सर ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से घबरा जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि काश में इसे पुराने तरीके से बदल पाता। उन्होंने उस समय को याद किया जब मजबूत आर्थिक डेटा से आमतौर पर फाइनंशियल मार्केट को बढ़ावा मिलता था। ट्रंप ने तर्क दिया कि आर्थिक विकास को अपने आप महंगाई बढ़ाने वाला नहीं माना जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने सरकार के तहत अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक रहस्य कहकर तत्वीर भी पेश की, और देश को स्वर्ण युग में बताते हुए कहा, ‘आज हमारे यहां पहले से कहीं ज्यादा फैक्ट्रियां बन रही हैं। आज हमारे देश के इतिहास में पहले से

कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी वर्कर पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं और कहा, ‘मैं अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सामान्य नौकरियां हैं और उनके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रेसिडेंट रहने के दौरान स्टॉक मार्केट बार-बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।अपने मौजूदा सरकार की तुलना अपने पहले टर्म से करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आर्थिक प्रदर्शन ने उनके पिछले कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पॉलिसीमेकर्स की भी आलोचना की और कहा कि वे ब्याज दर को बहुत ज्यादा रखकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा करने का रिस्क उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मुझे सच में लगता है कि मैं वापस आना चाहूंगा, जब आपने शानदार नंबरों की घोषणा की कि एक, तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया।

वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2,595 हुई, 12,000 से ज्यादा घायल

काराकास। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलेसी रोड्रिगेज ने कहा कि भूकंप से 2,595 लोग मारे गए हैं और 12,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा, देश में 189 इलाकों भूकंप के तेज झटकों की वजह से तबाह हो गई हैं।

कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज अस्थायी कैप बनाने के कमांड सेंटर की भी प्रमुख हैं। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य श्रमिकों, सुरक्षा कर्मचारियों और फायरफाइटर्स से भूकंप की वजह से घर की दिक्कतों को दूर करने के लिए पैट्रिया प्लेनर्याम पर रजिस्टर करने को कहा था।

उन्होंने कहा कि 25 अस्थायी कैप सक्रिय थे, जिनमें ला गुएरा में 13, काराकास में आठ, मिरांडा में दो, काराबोबो में एक और याराकूय में एक कैप शामिल हैं।

रोड्रिगेज ने कहा कि अधिकारी कैंपों की तैयार करने और प्रभावित लोगों को वहां भेजने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 जून से अब तक वेनेजुएला में 782 आप्रदर्शांक रिकॉर्ड किए गए हैं, हालांकि धीरे-धीरे इसमें कमी आई है। इसके अलावा, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी

रोड्रिगेज ने 24 जून को देश में आए शक्तिशाली भूकंप के पीछितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सात दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘पीड़ितों की याद में मैंने बुधवार (स्थानीय समय) की शाम 6:00 बजे से सात दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित करने का फैसला किया है। भारी दुख की इस घड़ी में हम इस त्रासदी से पीड़ित लोगों को गले लगाते हैं और उनके साथ रहने और उनकी रक्षा करने का अपना वादा दोहराते हैं।’

रुड्रिगेज ने आगे कहा, ‘खतरनाक भूकंपों से हुए मानव

जीवन के नुकसान से वेनेजुएला बुरी तरह दूट गया है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंगलवार तक भूकंप से कम से कम 1,943 लोगों की मौत हो चुकी थी और 10,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले, पुर्तगाली सरकार ने भी वेनेजुएला में भूकंप के पीड़ितों, खासकर पुर्तगाली नागरिकों और पुर्तगाली मूल के लोगों के लिए रविवार (5 जुलाई) को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की थी।

पाकिस्तान : बलूचिस्तान में भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत, कई घायल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में भारी मानसूनी बारिश के बाद झोब और खुजदार इलाकों में दो घरों की छतें ढहने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, मानसून से पहले की बारिश ने बलूचिस्तान के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि अचानक आई बाढ़ के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जो एक जिले को दूसरे से जोड़ती थीं। भारी बारिश के कारण घर, फसलें और बुनियादी ढांचा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

बाचा खान स्कूल के पास और झोब के शम्सी कालोनी में छत गिरने की घटनाएं हुईं, जहां भारी बारिश के बाद दो मिट्टी के घरों की छत गिर गई। स्थानीय प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि मलबे के नीचे दबने से एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में प्रभावित दोनों



परिवारों के करीब 10 से अधिक सदस्य घायल हुए है।

घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया, ‘बचावकर्मियों ने शवों को निकाला और घायलों को निकालकर झोब स्थित अस्पताल में भर्ती कराया।’

उन्होंने आगे बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को विशेष उपचार के लिए क्वेटा रेफर कर दिया गया है। फ्रिकिसा-कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। खुजदार जिले में बारिश से संबंधित एक घटना में एक बच्चे की मौत हो गई और चार अन्य

घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान के कारण मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त हो गए और पेड़ व होर्डिंग उखड़ गए। खराब मौसम के कारण क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। गुरुवार को रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता फारूक अहमद ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब में पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता ने बताया कि तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण दीवारों, छतों और एक होर्डिंग के गिरने से हताहत हुए।

अटक में दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। प्रवक्ता के अनुसार, पारा शाहीन बाग में एक घर की छत गिरने से तीन लोग घायल हो गए।

वेनेजुएला भूकंप : जान गंवाने वालों में इटली मूल के 16 लोग, पीएम मेलोनी ने बताया दुख

इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वेनेजुएला के विनाशकारी भूकंप को लेकर गहरा दुःख और संवेदना जताई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों में इटली मूल के 16 लोगों की भी पहचान हुई है। मेलोनी ने सभी को श्रद्धांजलि दी और प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में लगे लोगों के योगदान की सराहना भी की है।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिा‘या प्लेटफॉर्म ‘फ़क्स’ पर लिखा, ‘वेनेजुएला में आया विनाशकारी भूकंप अभी भी अपना दुःखद असर दिखा रहा है। इस हादसे में हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिनमें इटली मूल के 16 लोगों की भी पहचान हो चुकी है, जिनकी



मौत हो गई।’’ प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, ‘इटली की सरकार वेनेजुएला के लोगों और इस भारी त्रासदी से प्रभावित सभी परिवारों के साथ होने का भरोसा जताती है। इटली इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की मदद करने के लिए, दोस्ती और एकजुटता की भावना के साथ अपना योगदान देता रहेगा। ’

उन्होंने कहा कि हमारे बचाव कर्मियों के प्रति मैं गहरा आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी हिम्मत, आपका पेशेवर काम और जिस ईसानियत के साथ आपने इटली का प्रतिनिधित्व किया है, उस पर पूरा देश गर्व करता है। आपने जो किया है और आगे भी जो कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद।

चीन ने एआई से बाधा-मुक्त निर्माण के विषय पर संयुक्त भाषण दिया



ताकि ‘सभी के लिए सुलभता’ पर प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जा सके। संयुक्त भाषण में कहा गया है

विकलांगों, बुजुर्गों और अन्य कमजोर लोगों समेत सभी व्यक्तियों के लिए बहुत अहम है।

संयुक्त भाषण में चार सूत्रीय विचार पेश किए गए। पहला, एआई के जरिए सुलभता को बढ़ावा दें, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले विकास में

नई उम्मीद जग सके। दूसरा, एआई से सुलभता बढ़ाने में मानव को प्राथमिकता देते हुए कमजोर समूहों को सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की सहायता दें, ताकि सामाजिक विकास की उपलब्धियों का साझा किया जा सके। तीसरा, निष्पक्षता और न्याय में संलग्न रहें,

ताकि अलग-अलग समूह और देश सुलभ वातावरण तक पहुंच सके और चौथा, सहिष्णुता को प्रोत्साहित कर डिजिटल विभाजन व असंतुलित विकास कम करने के साथ एआई के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आदान-प्रदान करें।

बताया जाता है कि संयुक्त भाषण को व्यापक समर्थन मिला। रूस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला, थाईलैंड और कंबोडिया आदि कई देशों ने संयुक्त भाषण में भाग लिया। विकासशील देशों ने सक्रियता से अपना पक्ष रखा।

गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे सेमी ओएसएटी प्लांट का उद्घाटन

विश्व केसरी■

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह अहमदाबाद जिले के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन करेंगे।

इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत विकसित शुरुआती सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग संयंत्रों में से एक है, जहां व्यावसायिक उत्पादन की औपचारिक शुरुआत होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री राजस्थान के कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद शाम करीब 4:30 बजे साणंद पहुंचेंगे। उद्घाटन के बाद वह वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे।

करीब 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से तैयार किया गया यह प्लांट



इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर की गई पहली चार परियोजनाओं में शामिल है। यह अत्याधुनिक सुविधा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एंड-टू-एंड असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यहां वेफर सॉटिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइन, फेल्योर एनालिसिस, टेस्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोडक्ट

जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। साथ ही ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के बढ़ते उपयोग से मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती मांग को भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस सुविधा का उद्घाटन भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे देश वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा तथा घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम को नई ताकत मिलेगी।

गुजरात पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे और बालोतरा में करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

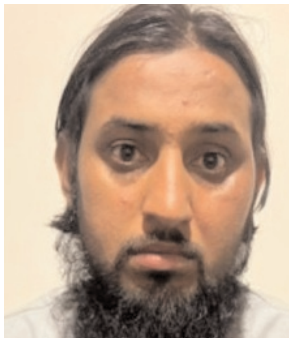
गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आठ सद्विग्ध गिरफ्तार

विश्व केसरी■

अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से कथित संबंध रखने और राज्य में संगठन का सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रचने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां गुजरात और मध्य प्रदेश में की गईं।

एटीएस के अनुसार, विस्तृत जांच के बाद गुरुवार को एटीएस पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए), 1967 की धाराएं 13, 17, 18, 38 और 39 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराएं 148 और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया।

एटीएस अधिकारियों ने दावा किया कि गिरफ्तार सभी आठ आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और राज्य में संगठन का सक्रिय नेटवर्क तैयार



कर उसकी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बनारसकांठा जिले के पालनपुर शहर के भागल निवासी अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू उबैदा (19), इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा उर्फ अबू हमजा (30), मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू आया (22), पाटन जिले के सिद्धपुर स्थित खडियासणा की जामिया अबुल हसन मदरसा के जकारिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ इब्न अम्मार उर्फ जकारिया पालनपुरी (21), उसी मदरसे के

मुफ्ती फौजान इस्माइल दौबा उर्फ मुफ्ती साहब (40), मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी (21), नवसारी जिले के चिखली के अंभेठा स्थित जामिया रहमानिया खंभिया के मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ मोहम्मद पालनपुरी उर्फ अबू उनीसा (22) तथा मध्य प्रदेश के देवास शहर के वारसी नगर निवासी बिलाल दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ अबू दुजाना, अबू सुफियान, अबू जुंजुल और उमर बिन खताब (18) के रूप में हुई है। एटीएस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एटीएस ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों के तहत कई अहम कार्रवाइयां की गई हैं। इसी वर्ष जनवरी में एटीएस और नवसारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक 22 वर्षीय युवक को नवसारी से गिरफ्तार किया था।

संक्षिप्त खबर

एक विधायक के साथ सरकार नहीं बन सकती’, डीएमके ने ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ आरोपों को बताया साजिश

चेन्नई। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) के प्रवक्ता टीकेएस इलांगोवन ने टीवीके विधायक को खरीदने का क्या तोड़ने की कोशिशों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है और विरोधी यह साबित करना चाहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए टीकेएस इलांगोवन ने कहा, ‘वे (टीवीके) यह कैसे कह सकते हैं कि डीएमके हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है? वे बस एक मामला बना रहे हैं। डीएमके एक विधायक को क्यों खरीदेंगे? इसका क्या फायदा है?’

उन्होंने कहा, ‘हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। हम सिर्फ एक विधायक के साथ सरकार नहीं बना सकते हैं और न ही वह एक

विधायक टीवीके प्रमुख विजय को हराने वाला है। फिर एक विधायक को खरीदने का क्या मकसद है? वे साजिश रच रहे हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं।’

टीकेएस इलांगोवन ने कहा, ‘उन्होंने (टीवीके) 35 करोड़ रुपए की बात कही है। 35 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मकसद है? उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हमें उसके चुनाव के लिए फिर से पैसा खर्च करना होगा। इन सब चीजों का क्या मकसद है? वे बस डीएमके पर यह आरोप लगाना चाहते हैं कि वे हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हैं।’

आईएडीएमके के डीएमके के साथ हाथ मिलाने की खबरों पर टीकेएस इलांगोवन ने कहा, ‘ये सरासर झूठ हैं। टीवीके किसी राजनीतिक पार्टी की तरह काम नहीं कर रही है।

ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। डीसीपी ने इसकी जानकारी दी है। साउथ के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया, ‘29 जून को दोपहर करीब 3 बजे साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टफ को सूचना मिली कि कोटला मुबारकपुर इलाके में तीन लोग भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ मिल सकते हैं। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई और तुरंत मौके पर भेजी गई। शाम करीब 6 बजे कोटला मुबारकपुर के एक घर से तीन लोगों को पकड़ा गया।’

डीसीपी के अनुसार, तलाशी लेने पर लगभग 8.6 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता की चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 से 9 करोड़ रुपए है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। तीनों आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं। बांटे कुछ वर्षों से देश में अलग-अलग जगहों पर काम कर चुके हैं। हिमाचल और गोवा में शेफ के तौर पर काम कर चुके हैं। जांच से पता चला है कि सोनौली बॉर्डर पर एक महिला इन लोगों को चरस हैंडओवर करती थी। डीसीपी की ओर से बताया गया कि ‘नशा मुक्त भारत’ के तहत नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत यह बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि टीम में महिला की तलाश में जुटी हुई हैं। महिला से पूछताछ के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे कि इसके पीछे कितना बड़ा गैंग है। उन्होंने बताया कि ज्योति पुनमगर सरगना है। इसके साथ ही भरत थापा और गोविंद बुद्धा नाम के युवक को पकड़ा गया है।

डिजिटल अरेस्ट टगी: सीबीआई की ओडिशा और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

विश्व केसरी■

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2.07 करोड़ रुपये के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर ठगी मामले में ओडिशा और राजस्थान में सात स्थानों पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज मामले की जांच के तहत की गई।

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2.07 करोड़ रुपये के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर ठगी मामले में ओडिशा और राजस्थान में सात स्थानों पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज मामले की जांच के तहत की गई। सीबीआई के अनुसार, एजेंसी ने 30 जून को ओडिशा और राजस्थान के सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में 25 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि साइबर ठगों ने खुद को कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों का अधिकारी बताकर एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को डराया-धमकाया और फर्जी कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर उससे 2.07 करोड़ रुपये अलग-अलग लेनदेन के जरिए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।

गिरफ्तार आरोपियों की

आम महोत्सवमें सीएम योगी बोले, केमिकल-मुक्त उत्पाद वैश्विक बाजार में बनाएंगे पहचान

विश्व केसरी■

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि को आधुनिक तकनीक, वैश्विक बाजार और गुणवत्ता आधारित उत्पादन से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित खेती, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और निर्यात को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश के आम को दुनिया के प्रमुख बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के आमों का अवलोकन किया और आम उत्पादकों से उनकी विशेषताओं



की जानकारी ली। इस दौरान प्रदर्शनी में रखा करीब आधा जिरी, बल्कि किसानों की उत्सुकता का केंद्र बना।

मुख्यमंत्री ने दोनों हाथों में आम लेकर तस्वीर भी खिंचवाई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पाद रसायन-मुक्त हों और गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्विक मानकों पर पूरी तरह खरे उतरें। इसके लिए

अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मलिहाबाद का दशहरी आम जीआई टैग मिलने के बाद वैश्विक पहचान हासिल कर चुका है। इससे न केवल इस क्षेत्र के उत्पादकों को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पादों की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए चार आधुनिक पैक हाउस स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने उल्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का आम ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मलेशिया और कुवैत सहित कई देशों में निर्यात किया जा रहा है।

कर्नाटक में शिकायतों के बाद घर-घर बांटे जाएंगे एसआईआर के फॉम



विश्व केसरी■

बेंगलुरु। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रप्र घर-घर जाकर बांटने के बजाय दफ्तरों से दिए जाने की शिकायतों के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी. अंबु कुमार ने शुक्रवार को सभी उपायुक्तों को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि रामनगर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कर्नाटक सरकार सीधे हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने मामले में कथित अनियमितताओं की तत्काल और निष्पक्ष जांच

कराने की मांग की।

इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि इस प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के सबूत हैं।

सभी उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को जारी निर्देश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि बृथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार हर घर जाकर गणना प्रप्र वितरित करें। ये प्रप्र सरकारी दफ्तरों या किसी अन्य तय स्थान से नहीं बांटे जाने चाहिए। यह निर्देश राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया है। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूची के चल रहे सत्यापन और प्रप्र वितरण के दौरान घर-घर जाकर काम करने के तय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोहराया कि एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ही सख्ती से संचालित किया जाना चाहिए और जिला प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे सभी बृथस्तरीय अधिकारियों द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

बंगाल के विधायकों से ओम बिड़ला बोले, समाधान खोजना ही एक आदर्श विधानसभा का लक्ष्य

विश्व केसरी■

कोलकाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी आदर्श राज्य विधानसभा का मुख्य उद्देश्य सार्थक चर्चा करने और सुर्दों को पहचानने के अलावा, मौजूदा समस्याओं का समाधान खोजना भी होना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने परिचय बंगाल विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम (परिचय कार्यक्रम) के उद्घाटन के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा कि आम लोगों को विधायक से बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। विधायक की भूमिका, मौजूदा कानून और लोगों की उम्मीदें व हालात, ये सभी राज्य के विकास से जुड़े हैं। इसलिए, एक आदर्श विधानसभा वह जगह है जहां समाधान खोजे जाते हैं, चर्चाएं होती हैं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। पुरानी सभी चर्चाओं



और बहसों को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को सलाह दी कि वे राज्य विधानसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जानकारी पर आधारित चर्चाओं पर ध्यान दें और साथ ही सीखने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया में भी शामिल रहें।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको जानकारी के आधार पर सुर्दों और विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। आपको अपनी टीम और देश का नेतृत्व करना चाहिए। आपको सीखना है और और अधिक सीखना है। आपके अंदर

सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीखने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। आपको उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के फायदे के लिए कुछ नया करना सीखना चाहिए जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से अपडेट रहने के लिए डिजिटल लर्निंग पर ध्यान देने की भी सलाह दी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें, तो दूसरे देशों के बजट प्रस्तावों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जब तक हो सके विधानसभा में रहें। जब तक आप विधानसभा में रहेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। आपकी रुचि बढ़ेगी। चाहे आपको बोलने का मौका मिले या न मिले, सीखने के लिए विधानसभा में बने रहें।

एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहा था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने इसी तरह शिकायतकर्ता और कई अन्य लोगों को धोखा

दिया, उनसे लाखों रुपये लिए और उन्हें जाली जांच ऑफर लेटर, वीजा, हवाई टिकट और अन्य नकली दस्तावेज दिए। इस योजना को

विश्वसनीय बनाने के लिए पीडितों से ऑनलाइन इंटरव्यू और मेडिकल जांच करवाई गई और उनसे एग्जिमेंट भी साइन कराए गए। हालांकि, कोई नौकरी नहीं मिली और न ही पैसे वापस किए गए। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, न्यायिक फैसले के लिए सक्षम अदालत के सामने चार्जशीट पेश की गई। क्राइम ब्रांच ने आम जनता को आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने और ऐसी किसी भी घटना को सूचना एसएसपी, ईओडब्ल्यू कश्मीर, क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर को देने की सलाह दी है। आर्थिक धोखाधड़ी के पीडित अपनी शिकायत आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं।

कैसे बीएटी-बीएमएस और इसके जैसे ऐप के माध्यम से दूर से ही स्विच ऑफ हो रहे थे ई-रिक्शा, सरकार ने किया बैन



विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर ऐप के माध्यम से दूर से ही ई-रिक्शा स्विच ऑफ करने के कई वीडियो वायरल होने के बाद चीनी ऐप बीएटी-बीएमएस को मिलाकर कई ऐप जांच के दायरे में आ गए हैं। इसकी वजह सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और ऐप के दुरुपयोग की संभावनाएं हैं।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से बीएटी-बीएमएस समेत लासिगी और एपीच आई-आयन ऐप हटाने का आदेश दिया है।

सेहत जैसे जरूरी पैरामीटर्स को रियल-टाइम में मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा, यह ऐप यूजर्स को मैनेज करने की सुविधा भी देता है, जिसमें रखरखाव और सुरक्षा के लिए बैटरी के डिस्चार्ज फीचर्स को चालू या बंद करना शामिल है।

भारत में कई ई-रिक्शा बनाने वाली कंपनियां ब्लूटूथ-आधारित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) वाली लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल करती हैं। कई ई-रिक्शा में ये सिस्टम बिना पासवर्ड सुरक्षा के लगाए जाते हैं या फैक्टरी-डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही काम करते रहते हैं।

इससे 10 से 20 मीटर की रेंज के साथ ब्लूटूथ ऑन रहता है। कोई भी व्यक्ति बीएटी-बीएमएस या इसके जैसे किसी अन्य ऐप का उपयोग करके ई-रिक्शा को स्विच ऑफ कर सकता है।

समाचार एजेंसी आईएनएस से ??बात करते हुए, एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि यह समस्या कुछ दिन पहले ही सामने आई, जब उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई।

ड्राइवर ने कहा, 'शुरू में हमें लगा कि गाड़ी में कोई खराबी है और हम उसे मैकेनिक के पास ले गए। जांच करने के बाद, उसने बताया कि कोई मैकेनिकल समस्या नहीं है। उसने कहा कि किसी ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बैटरी बंद कर दी थी।'

उसके मुताबिक, मैकेनिक ने मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए बैटरी को फिर से कनेक्ट करने और फिर से शुरू करने के लिए लगभग 300 रुपए लिए।

उन्होंने कहा, 'उन्होंने अपने फोन पर ऐप खोला, बैटरी को फिर से चालू किया और गाड़ी दोबारा चलने लगी।'

ड्राइवर ने दावा किया कि जब वह यात्रियों को ले जा रहे थे, तब यह समस्या फिर से हुई। 'जब मैं सड़क पर था, तो किसी ने इसे फिर से बंद कर दिया। हमें नहीं पता कि ऐसा कौन कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर बैटरी लॉक हो जाती है, तो इसे सिर्फ उसी ऐप से अनलॉक किया जा सकता है। हम ड्राइवर हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए।

हालांकि, यह खतरा सिर्फ उन गाड़ियों तक सीमित है जो दो शर्तें पूरी करती हैं। उनमें ब्लूटूथ-आधारित लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में पासवर्ड प्रोटेक्शन या सही ऑथेंटिकेशन की कमी होती है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत के जीसीसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा भागीदार बना जापान, 100 से अधिक सेंटर स्थापित

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जापान एशिया-प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र में भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) इकोसिस्टम का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। जापानी कंपनियां भारत में 100 से अधिक जीसीसी स्थापित कर चुकी हैं और ये सेंटर अब इंजीनियरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं।

डेलॉइट इंडिया की 'इंडियाज स्ट्रेटेजिक जीसीसी प्ले फॉर जापानीज इंटरप्राइजेज' नामक रिपोर्ट के अनुसार, जापानी कंपनियां एनोवेशन-आधारित और क्षमता-केंद्रित विकास को गति देने के लिए भारत में अपने जीसीसी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एम्बेडेड सिस्टम, क्लाउड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एनालिटिक्स और डिजिटल मैनुफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर और जीसीसी इंडस्ट्री लीडर लोबो ने कहा कि जैसे-जैसे जापानी कंपनियां अपने वैश्विक क्षमता नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं, भारत उनके लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर उपलब्ध इंजीनियरिंग प्रतिभा,

महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा। अहमदाबाद, जयपुर, कोयंबटूर, कोच्चि और इंदौर जैसे उभरते शहर भी तेजी से जीसीसी निवेश के नए केंद्र बन रहे हैं। इन शहरों में कम लागत, विशेष कौशल वाले प्रतिभा समूह और राज्य सरकारों की उद्योग समर्थक नीतियां इस विस्तार को गति दे रही हैं।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर कीर्ति कुमार ने कहा कि भारत में जापानी जीसीसी मुख्य रूप से इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों पर केंद्रित हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र की 15 प्रतिशत, जबकि ऑटोमोबाइल और हेल्थकेयर सेक्टर की 11-11 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

क्या हाई ब्लड प्रेशर बदल सकता है आपका व्यक्तित्व? नई स्टडी में सामने आया चौंकाने वाला दावा

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) को लंबे समय से दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी समस्याओं का बड़ा कारण माना जाता रहा है। डॉक्टर हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि यह अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ता रहता है। यही वजह है कि इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है। लेकिन अब एक नई स्टडी में हाई ब्लड प्रेशर को लेकर एक बड़ी



चौंकाने वाली बात सामने आई है। हाल ही में जर्नल 'जनरल साइकियाट्री' में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, हाई ब्लड प्रेशर का असर सिर्फ दिल और रक्त वाहिकाओं तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि यह इंसान के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर ब्लड प्रेशर की निचली रीडिंग, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, का संबंध नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी व्यक्तित्व विशेषताओं से पाया गया है।

ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) को दो पैमानों पर मापा जाता है। पहली यानी ऊपर की संख्या को 'सिस्टोलिक' ब्लड प्रेशर करते हैं, जो दिल के धड़कने और शरीर में खून पंप होने के दौरान नसों के दबाव को दर्शाती है। वहीं, दूसरी यानी नीचे की संख्या 'डायस्टोलिक' ब्लड प्रेशर कहलाती है। यह उस समय का दबाव मापती है जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम की स्थिति में होता है। हाल ही में हुए एक नए शोध में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हमारे व्यक्तित्व

पर सिस्टोलिक के मुकाबले डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का असर कहीं अधिक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने जिस व्यक्तित्व गुण का अध्ययन किया, उसे 'न्यूरोटिसिज्म' कहा जाता है। जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म का स्तर ज्यादा होता है, वे छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा चिंता करते हैं, तनाव जल्दी लेते हैं, खुद पर संदेह करते हैं और नकारात्मक भावनाओं से जल्दी घिर जाते हैं। ऐसे लोग आलोचना को भी ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में उन्हें अधिक कठिनाई होती है। यही नहीं, ऐसे लोगों में आगे चलकर चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का खतरा भी अधिक हो सकता है। इस संबंध को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे 'मेंडेलियन रैंडमाइजेशन' कहा जाता है। इस पद्धति में इंसानों के जीन का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश की जाती है कि कोई संबंध वास्तव में कारण और परिणाम का है या सिर्फ संयोग है। वैज्ञानिकों ने ब्लड प्रेशर से जुड़े एक हजार से अधिक आनुवंशिक संकेतकों का विश्लेषण किया और यूरोपीय मूल के लोगों पर आधारित आठ बड़े अध्ययनों के आंकड़ों का अध्ययन किया।

शोध में यह सामने आया कि जिन लोगों का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अधिक था, उनमें न्यूरोटिसिज्म का स्तर भी ज्यादा देखने को मिला। यानी हाई ब्लड प्रेशर और नकारात्मक भावनाओं के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया।

राजस्थान में सिजेरियन प्रसव में इस्तेमाल होने वाले बुपिवाकेन इंजेक्शन की बिक्री, उपयोग पर लगा प्रतिबंध



विश्व केसरी ■
जयपुर। हैदराबाद के एक अस्पताल में मरीजों में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव (एडवर्स रिएक्शन) सामने आने की रिपोर्ट के बाद राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग ने बुपिवाकेन (इंजेक्शन के एक विशेष बैच की बिक्री और उपयोग पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है।

सिजेरियन प्रसव सहित विभिन्न प्रकार की सर्जरी के दौरान स्पाइनल

मेडिकेयर लिमिटेड द्वारा निर्मित बुपिवाकेन इंजेक्शन का इस्तेमाल तत्काल बंद करने की अपील की है। इस एडवाइजरी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने सभी अस्पताल अधीक्षकों और विभागाध्यक्षों (एचओडी) को संबंधित इंजेक्शन का उपयोग तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान के औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि प्रभावित इंजेक्शन 'बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन डेक्सट्रोज' है, जिसका निर्माण थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड ने किया है। इसका इस्तेमाल नियमित रूप से सर्जरी के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए किया जाता है।

उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक एहतियात के तौर पर राजस्थान में इस इंजेक्शन की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।

विभाग ने अधिकारियों को प्रभावित बैच के साथ-साथ इस उत्पाद के अन्य बैचों के नमूने भी प्रयोगशाला जांच के लिए एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।

बारिश के मौसम में सेहत का रखें खास ख्याल, ऋतुचर्या के अनुसार बदलें खान-पान और दिनचर्या की आदतें

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। वर्षा ऋतु का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी लेकर आता है, लेकिन इसी समय शरीर के अंदर कई बदलाव भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, इस मौसम में पाचन शक्ति, यानी जठराग्नि, थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए जो भी हम खाते-पीते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी वजह से ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है, ताकि शरीर संतुलित और रोगों से सुरक्षित रह सके।

आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस मौसम में हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा होता है। भारी, तला-भुना और बासी खाना पाचन को और कमजोर कर सकता है। बरसात में नमी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए बाहर का या खुला हुआ खाने से बचना चाहिए। घर का बना सादा भोजन, जैसे मूंग दाल, उबली हुई सब्जियां और हल्के मसालों वाला खाना शरीर के लिए बेहतर माना जाता है।

आयुर्वेद यह भी कहता है कि इस मौसम में खट्टा और नमकीन स्वाद सीमित मात्रा में लेना चाहिए। वहाँ, दूध और दही जैसी चीजों का सेवन

सोच-समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये कफ को बढ़ा सकती हैं और जुकाम या भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ा सकती हैं।

पानी पीने के तरीके में भी बदलाव जरूरी है। इस मौसम में उबला हुआ या हल्का गुनगुना पानी पीना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। सुबह की शुरुआत अगर गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर की जाए तो यह शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन को सुधारने में मदद करता है।

वर्षा ऋतु में योग और हल्का व्यायाम भी बहुत लाभदायक होता है।

इससे शरीर सक्रिय रहता है और जठराग्नि संतुलित बनी रहती है। वज्रासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन और पादहस्तासन जैसे आसान योगासन इस मौसम में विशेष रूप से उपयोगी माने जाते हैं।

इसके साथ ही साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ताजे फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खानी चाहिए।



ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एच5एन1 बर्ड फ्लू का पहला संदिग्ध मामला आया सामने

विश्व केसरी ■
सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) राज्य के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें देश के पूर्वी तट पर जानलेवा एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा का पहला संदिग्ध मामला मिला है।

न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की कृषि मंत्री तारा मोरियाटी ने बताया कि सिडनी से लगभग 165 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित तटीय कस्बे हॉक्स नेस्ट के पास बीमार मिले एक प्रवासी जायंट पेट्रेल पक्षी से लिए गए नमूनों की

पूर्वी तट पर इसका पहला मामला होगा। पिछले सभी पांच मामले जून में प्रवासी पक्षियों में पाए गए थे, जिनमें से चार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में था।

मोरियाटी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को संदिग्ध मामले के बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा, 'हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री पर असर पड़ने की कोई जांच में संक्रमण की पुष्टि होती है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई मुख्यभूमि के एच5एन1 स्ट्रेन का छटा और देश के



फीफा वर्ल्ड कप: स्विट्जरलैंड ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, अल्जीरिया को 2-0 से हराया



विश्व केसरी ■
वैंकूवर। स्विट्जरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। बीसी प्लेस स्टेडियम में हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 2-0 से हराया।
स्विट्जरलैंड की ओर से इस मुकाबले में ब्रिल एम्बोलो और डैन नडोये ने गोल दागे। मैच की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड ने आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में

जोहान मंजांबी ने शानदार दौड़ लगाते हुए गेंद को पेनल्टी बॉक्स के अंदर पहुंचाया। मंजांबी से मिले पास को ब्रिल एम्बोलो ने गोल में तब्दील करके स्विट्जरलैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ में अल्जीरिया ने भी कुछ अच्छे हमले किए, लेकिन टीम स्विट्जरलैंड के डिफेंस को नहीं भेद सकी। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बहुत दोगुनी कर दी। खेल शुरू होने के एक मिनट के अंदर ही डेनिस जकारिया का क्रॉस अल्जीरिया की

टीम ठीक से क्लियर नहीं कर सकी। गेंद डैन नडोये के पास पहुंची, जिन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। यह वर्ल्ड कप में नडोये का पहला गोल था और उन्होंने खास अंदाज में इसका जश्न मनाया।
2-0 से पीछे होने के बाद अल्जीरिया मैच में वापसी नहीं कर सका। टीम ने कुछ कोशिशें जरूर कीं, लेकिन वह कोई बड़ा मौका नहीं बना पाई। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और अपनी बहुत सुरक्षित रखी। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इससे पहले, टीम ने ग्रुप चरण में बोस्निया और हर्जगोविना तथा कनाडा को हराया था। यह पहला मौका है जब स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड कप में लगातार तीन मैच जीते हैं।
स्विट्जरलैंड 17 मुकाबलों में सिर्फ एक हार के साथ इस मैच में उतरा था, और टीम ने अपनी जबरदस्त लय को अल्जीरिया के खिलाफ भी बनाए रखा। अब स्विट्जरलैंड का अगला मुकाबला 7 जुलाई को कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इस मुकाबले की मेजबानी भी वैंकूवर ही करेगा। स्विट्जरलैंड लगातार तीसरी बार वैंकूवर में खेलेगा, और टीम को निगाहें जीत की हैट्रिक पर होंगी।



सोफी एक्लेस्टोन ने रचा इतिहास, महिला टी20 विश्व कप में बनी सर्वाधिक विकेट लेने वाली स्पिनर



विश्व केसरी ■
लंदन। महिला टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराया। इंग्लैंड ने पांचवीं बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट हासिल किया है। अमेरिलिया केर को पीछे छोड़ा। केर ने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 37 विकेट निकाले हैं। वहीं, इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की गेंदबाज स्टेफनी टेलर 33 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। एक्लेस्टोन ने सेमीफाइनल मुकाबले में क्लो ट्रायोन को बेहतरीन गेंद पर क्लीन बॉलड करने

के साथ ही इतिहास रचा। वह महिला टी20 विश्व कप में अब सर्वाधिक विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाज बन गई हैं। एक्लेस्टोन टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 38 विकेट चटका चुके हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड की कसान अमेरिलिया केर को पीछे छोड़ा। केर ने टी20 वर्ल्ड कप में कुल 37 विकेट निकाले हैं। वहीं, इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की गेंदबाज स्टेफनी टेलर 33 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। एक्लेस्टोन टी20 विश्व कप 2026 में खेले अब तक 6 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुकी हैं।

एशियन गेम्स 2026 से पहले विजयी भारत फाउंडेशन से जुड़ीं ओलंपियन भवानी देवी

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। सैंबर तलवारबाज सी.ए. भवानी देवी एशियन गेम्स 2026 से पहले विजयी भारत फाउंडेशन (वीबीएफ) में शामिल हो गई हैं। वह वीबीएफ के उच्च-प्रदर्शन तलवारबाजी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी।
भवानी देवी टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर (तलवारबाज) बनी थीं। भवानी का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में दमदार रहा था और उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी ने अपने दमदार खेल के बूते गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 2022 में भी वह अपने इस प्रदर्शन को दोहराने में सफल रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने 2023 में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
टोक्यो ओलंपिक में भवानी ने महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राउंड



ऑफ 32 तक का सफर तय किया था। उन्होंने राउंड ऑफ 64 में ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को एकतरफा मुकाबले में 15-3 से शिकस्त दी थी। हालांकि

अनुभव मिला है, जो वीबीएफ की टैलेंट पाइपलाइन में युवा फेंसर्स की भी मदद करेगा।
इस एसोसिएशन के बारे में बात करते हुए भवानी ने कहा, 'मैं विजयी भारत फाउंडेशन और उनकी टीम से जुड़कर बहुत खुश हूँ। मैं उनके खेल विकास कार्यक्रम, खासकर फेंसिंग के बारे में बहुत अच्छी खबरों को फॉलो कर रही हूँ। मैं उनके सपोर्ट से आने वाले एक रोमांचक सीजन का इंतजार कर रही हूँ।'
भवानी ने हाल ही में दिल्ली में एशियन सैनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था, जिसका हिस्सा विजयी भारत फाउंडेशन के सात फेंसर्स की रहे थे। भवानी देवी के ओलंपिक तक का सफर तय करने के चलते भारत में तलवारबाजी के खेल को पहचान भी मिली। भवानी नेशनल लेवल पर 9 बार चैंपियन रह चुकी हैं। भवानी को साल 2021 में भारतीय सरकार द्वारा 'अर्जुन पुरस्कार' से भी नवाजा जा चुका है।

हम लगभग हर तरह से परफेक्ट थे, लेकिन आगे के मुकाबले और चुनौतीपूर्ण होंगे: स्पेनिश हेड कोच

विश्व केसरी ■
लॉस एंजिल्स। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इस जीत के बाद स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फुएंते ने टीम के प्रदर्शन को लगभग परफेक्ट बताया। हालांकि, उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि आगे के मुकाबले और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे।
मैच में स्पेन की ओर से पेद्रो पोरो ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया, जबकि मिकेल ओयाराजाबल ने दो गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिलाई। मुकाबले में स्पेन पूरी तरह से हावी नजर आया और टीम ने ऑस्ट्रिया को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 'सिन्हुआ' के मुताबिक डे ला फुएंते ने मैच के बाद कहा, 'बड़ी टीमों में तब सामने आती हैं जब उनकी मौजूदगी की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि आज हमने एक शानदार मैच देखा है। मैं खुश हूँ, क्योंकि हर तरह से हम लगभग परफेक्ट रहे, लेकिन हमें सुधार

करते रहना होगा। अब हर मैच बहुत मुश्किल होने वाला है।' क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए स्पेन का सामना अब पुर्तगाल से 7 जुलाई को होगा।
कोच ने मिकेल ओयाराजाबल की खास तारीफ की। उन्होंने बताया कि ओयाराजाबल ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में दो गोल करके इतिहास रच दिया है। वह 1986 के बाद पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने नॉकआउट मैच में एक से ज्यादा गोल किए हैं। इस टूर्नामेंट में ओयाराजाबल अब तक चार गोल कर चुके हैं और सऊदी अरब के खिलाफ ग्रुप मैच में भी उन्होंने दो गोल किए थे। डे ला फुएंते ने ओयाराजाबल को एक बेहतरीन खिलाड़ी बताते हुए कहा कि वह बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन साथ ही बेहद साधारण और जमीन से जुड़े इंसान भी हैं। इस मैच में स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 519 मिनट तक बिना गोल खाए खेलने का रिकॉर्ड बनाया।

फीफा वर्ल्ड कप: क्रोएशिया को हराकर पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में, रोनाल्डो-रामोस ने किए गोल



विश्व केसरी ■
टोरंटो। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 का टिकट हासिल कर लिया है। टोरंटो स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने

क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पुर्तगाल का राउंड ऑफ 16 में अब 7 जुलाई को स्पेन से सामना होगा। इस हार के साथ ही क्रोएशिया का वर्ल्ड कप में सफर समाप्त हो गया है। मैच की शुरुआत

में दोनों ही टीमों का डिफेंस काफी मजबूत नजर आया। पुर्तगाल ने एक के बाद हमले करते हुए क्रोएशिया के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया।
मैच के 10वें मिनट में रोनाल्डो हेडर की मदद से गोल करने का एक आसान मौका चूक गए। पहले हाफ में गेंद ज्यादातर पुर्तगाल के पास ही रही, लेकिन टीम शुरुआती 45 मिनटों में कोई गोल नहीं कर सकी। पुर्तगाल का पजेशन 60 प्रतिशत रहा, तो क्रोएशिया का पजेशन 28 प्रतिशत के करीब रहा।
पहले हाफ में पुर्तगाल ने 9 बार गोल करने का प्रयास किया, लेकिन टीम क्रोएशिया के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सकी। वहीं, क्रोएशिया की ओर से शुरुआती 45 मिनटों में गोल करने की तीन बार कोशिश की गई। हालांकि, मैच का दूसरा हाफ रोमांच से भरा रहा। मैच के 53वें

मिनट में ही इवान पेरेसिच ने शानदार गोल दागते हुए क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि, पुर्तगाल ने क्रोएशिया की बढ़त को ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने दिया। मैच के 64वें मिनट में पुर्तगाल के कॉर्नर पर क्रोएशिया के खिलाड़ी निकोला वालसिच ने पुर्तगाल के प्लेयर वेगा को रोकने का प्रयास किया। रेफरी ने वीएआर से जांच के बाद पाया कि निकोला ने जानबूझकर वेगा को रोकने की कोशिश की और पुर्तगाल को पेनल्टी मिल गई। रोनाल्डो ने पेनल्टी का पूरा फायदा उठाते हुए बेहतरीन गोल दागा और स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के नॉकआउट मुकाबले में रोनाल्डो का यह पहला गोल भी रहा। मैच के 81वें मिनट में रोनाल्डो की जगह पर रुबेन नेवेस को मैदान पर उतारा गया।

चिराग शेटी: कोच का एक फैसला बना वरदान, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में जीता स्वर्ण पदक

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। चिराग शेटी की गिनती भारत के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ियों में की जाती है। महज 7 साल की उम्र में चिराग को इस खेल से लगाव हो गया था। हालांकि, सिंगल्स में चिराग के हाथ लगातार नाकामा लगी, लेकिन 2016 में कोच के एक फैसले ने उनके करियर और जिंदगी को पलटकर रख दिया।
चिराग का जन्म 4 जुलाई, 1997 को मुंबई के मलाड में हुआ। बचपन से ही चिराग को बैडमिंटन खेलने का शौक था। जल्द ही उन्होंने इस खेल में करियर बनाने का फैसला कर लिया। इस खेल को करीब से जानने और बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में स्थित उदय पवार बैडमिंटन अकादमी में दाखिला लिया। इसके थोड़े समय बाद ही वह मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हो गए और



उन्होंने पुलेला गोपीचंद अकादमी में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। हालांकि, चिराग को शुरुआती करियर में सिंगल्स में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। जूनियर इंटरनेशनल सर्किट में उन्होंने एमआर अर्जुन के साथ मिलकर जोड़ी बनाई और दमदार किया। मगर चिराग की कामयाबी का सफर साल 2016 में कोच किम टैन हेर के एक फैसले के

सात्विक के साथ मिलकर कई बड़ी उपलब्धियों को अपने नाम किया। चिराग-सात्विक की जोड़ी ने साल 2019 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर ओपन, इंडोनेशिया ओपन सुर 1000 और कोरिया ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी अपने नाम किया।
चिराग के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2022 और 2023 में आई। 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में चिराग ने सात्विक के साथ मिलकर स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। वहीं, 2023 के एशियाई खेलों में भी चिराग-सात्विक का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जोड़ी ने यहां भी स्वर्ण पदक जीता। चिराग सात्विक संघ विश्व चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक जीतने में भी सफल रहे।